www.ghoonghatkibagawat www.ghoonghatkibagawat ghoonghatkibagawat37@gmail.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 46 गोरखपुर, 01 जून 2025 रविवार पृष्ठ : 6 मूल्य : 2

शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से भारत से पिटने की बात स्वीकारी

पाकिस्तान कुछ समझ पाता..ब्रह्मोस ने मचा दिया तांडव



पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना है कि 9-10 मई की रात को जब भारत ने रावलपिंडी के हवाई अड्डे सहित प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रक्षेपण किया। उनकी सेना को इस बात का अंदाजा नहीं था। अजरबैजान में एक कार्यक्रम में बोलते हुए शरीफ ने कहा कि असीम मुनीर के नेतृत्व वाली सेना ने 10 मई को सुबह की नमाज के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी। हालांकि, प्रधानमंत्री ने कहा कि भोर से पहले ही लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों पर हमला कर दिया। शरीफ ने कहा कि उन्हें सुबह-सुबह हुए हमले की जानकारी मुनीर ने दी, जिन्हें अब फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है। शरीफ ने लचिन में अपने भाषण के दौरान कहा कि 10 मई की रात को हमने भारतीय आक्रामकता का जवाब नपे-तुले अंदाज में देने का फैसला किया। हमारे सशस्त्र बल सुबह फज्र की नमाज के बाद 4.30 बजे कार्रवाई करने के लिए तैयार थे, ताकि सबक सिखाया जा सके। लेकिन उस समय से पहले ही भारत ने एक बार फिर ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल हमला किया, जिसमें रावलपिंडी के हवाई अड्डे सहित पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों को निशाना बनाया गया। भारत की सैन्य प्रतिक्रिया के बारे में प्रधानमंत्री की दुर्लभ स्वीकृति असीम मुनीर की मौजूदगी में आई।

रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस उन 11 सैन्य स्थलों में से एक था, जिन्हें भारत ने पाकिस्तान द्वारा पश्चिमी सीमा पर नागरिक क्षेत्रों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित इस एयरबेस में लॉकहीड सी-130 हरक्यूलिस और इल्यूशिन आईएल-78 रिफ्यूलर जैसे शीर्ष सैन्य विमान मौजूद हैं। सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम दो सैन्य परिवहन वाहनों को नुकसान पहुंचा है। नूर खान के अलावा, भारत ने रफीकी, मुरीद, रहीम यार खान, सुक्कुर और चुनियन में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। स्कार्दू, भोलारी, जैकबाबाद और सरगोधा में स्थित एयरबेस को भी भारी नुकसान पहुंचा।

जिन्ना का व्हाइट पेपर, हो गया भारत-पाक का बंटवारा

ये मैला सा उजाला, ये रात की आहत सुबह
जिसका इंतजार था हमे ये वो सुबह तो नहीं

फैज अहमद फैज ने अपनी कविता में लिखा था। ये आजादी की सुबह की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस जहां भारत के लिए एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी तो वहीं दूसरी तरफ देश का भयंकर बंटवारा भी हुआ था। बंटवारे के बारे में आप किसी से पूछोगे तो लोगों के पास कई सारी जबरदस्त कहानियां सुनाने को होती है। उनमें से ही एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आती है कि पंडित नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और एडविना माउंटबेटन को लेकर है। ये तीनों लंदन के हैरिस कॉलेज में साथ पढ़े थे। इन तीनों के बीच एक लव ट्रांगल चल रहा था। फिर एडविना ने अपने पति लुईस माउंटबेटन से जाकर कहा कि भारत का विभाजन कर दो जिससे नेहरू और जिन्ना दोनों प्रधानमंत्री बन सके। हालंकि ये फैक्चुअल रूप से सरासर गलत है क्योंकि जिन्ना ने अपनी लॉ की पढ़ाई लिंकन इन 1892 में जब कि थी तो नेहरू महज 3 साल के थे। वहीं एडविना तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। बहरहाल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से निकलकर वास्तविकता की ओर चलते हैं। देश को आजादी मिल गई थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि देश का विभाजन करना पड़ा। बड़े से बड़े दिग्गज इसे रोक क्यों नहीं पाए। बंटवारे को 78 साल हो चुके हैं। लेकिन आज भी आपको लोग ये बहस करते हुए दिख जाएंगे कि बंटवारा हुआ वो सही हुआ या गलत। क्या सच में ऐसी कोई चीज हो सकती थी जो इस बंटवारे को रोक देती। इसका जिम्मेदार कौन था? जिस तरह से हमारे लिए जिन्ना विलेन है उसी तरीके से आप पाकिस्तान में जाकर बात करोगे तो नेहरू और महात्मा गांधी को गलत बताया जाता है। कुछ का ये भी मानना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी बोस होते तो इस मुद्दे को वहीं पर सॉल्व कर लिया गया होता। बंटवारा नहीं होता तो वो खूनखराबा, जिसने 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली वो भी नहीं होता। ऐतिहासिक किरदारों और घटनाओं को लेकर हमेशा अटकलें और अनुमान लगाई जाती रही हैं। अंग्रेजी का एक जुमला 'व्हाट इफ' यूं होता तो क्या होता? क्या 1947 में देश का बंटवारा रोका जा सकता था? पिछले 78 सालों से ये सवाल देश को कचोटता रहा है। ऐसे में एक एक डिटेल मैं आपके सामने रखूंगा। जिससे की अगली बार जब आपके सामने कोई बंटवारे की बात करे तो आपको सही तथ्यात्मक जानकारी हो।

16 अगस्त 1946 की एक तारीख ने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी

पन्नों में वर्षों का हिसाब सिमट जाता है और वर्षों का हिसाब रखने वाली शख्सियतें गजों में दफ्न हो जाती है। हिन्दुस्तान के इतिहास ने भी ऐसे ही कद्दावर नेता देखें हैं। जिनका असर आम लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। मोहनदास करमचंद गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 16 अगस्त 1946 की एक तारीख हिन्दुस्तान की आजादी के इतिहास की ऐसी ही तारीख है जिसने बंटवारे की हकीकत पर मुहर लगा दी। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अपने स्वार्थ के लिए एक धड़े ने भारत को बांटने का दावा पेश कर दिया था। उनकी मांग थी पश्चिम के पेशावर से लेकर पंजाब के अमृतसर और कोलकाता समेत एक अलग राष्ट्र जो सिर्फ मुसलमानो के लिए बनेगा और जिसका नाम होगा पाकिस्तान। डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश, एक विधान, एक निशान और एक संविधान का नारा पूरे देश में गूंज रहा था। लेकिन मुस्लिम लीग की डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा ने पूरे देश को आग से खेलने पर मजबूर कर दिया था। जिन्ना ने कहा कि अगर समय पर बंगाल का सही फैसला नहीं मिला तो...हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। भारत से हमें कोई लेना-देना नहीं। हमें तो पाकिस्तान चाहिए, स्वाधीन पाकिस्तान चाहे भारत को स्वाधीनता मिले या न मिले। गोली और बम की आवाज से कांप उठी थी भारत मां की धरती। पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला। मुस्लिम बहुल इस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ था। कलकत्ता में 72 घंटों के भीतर 6 हजार से अधिक लोग मारे गए थे। 20 हजार से अधिक घायल हो गए थे। 1 लाख से अधिक बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है।

पाकिस्तान पर मुहर लगवाने के लिए क्या-क्या हथकंडे अपनाए

2 जून 1947, नॉर्थ कोट, नई दिल्ली: जब मीटिंग के बाद जब जिन्ना उठे तो मेज पर सादा कागज छोड़ गए। उस कागज पर रॉकेट, टेनिस रैकेट, उड़ते हुए गुब्बारों की तस्वीर के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था- गवर्नर जनरल। मतलब साफ था कि जिन्ना को गवर्नर जनरल बनना था लेकिन भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना था। मीटिंग के बाद जिन्ना मेज पर सादा कागज छोड़ गए थे वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा बुलाई गई थी। बैठक में माउंटबेटन के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना मौजूद थे। जाहिर था कि 2 जून 1947 की तारीख तक जिन्ना अपने भावी पदनाम के बारे में सोच चुके थे। जिन्ना को बखूबी पता था कि गवर्नर जनरल का पद उन्हें हिन्दुस्तान में नहीं मिल सकता। इसलिए इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए जिन्ना पाकिस्तान बनाने की खूनी जिद पाल चुके थे।



जिन्ना ने मजहबी एजेंडे को मजबूती से थामा

गांधी जी भारत का बंटवारा किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग थी जो मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। भारतीयों को सत्ता सौंपने के उद्देश्य से 24 मार्च 1947 को ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजा। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस और लीग नेताओं से चर्चा शुरू की। उस वक्त समूचे हिन्दुस्तान में कांग्रेस का दबदबा था। महात्मा गांधी सबसे बड़े लीडर थे जिनके सहयोगी पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम जैसे नेता। दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी पर मुस्लिम लीग की बेशुमार पकड़ थी। मोहम्मद अली जिन्ना इसके सुप्रीम नेता था। 1940 के दशक में जिन्ना ने बहुत ही चालाकी के साथ अपना राजनीतिक भविष्य तैयार किया। उन्हें पता था कि कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं है। क्योंकि मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक राजनीति को गांधी जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने लॉजिक दिया कि बहुसंख्यक रूप से हिंदू हैं और चुनाव होंगे तो हिंदू जीतेगा। कानून भी हिंदू ही बनाएगा तो ऐसी सूरत में मुस्लिम कहां जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हिंदू पार्टी है। 6 % नेताओं को छोड़ दिया जाए तो सारे हिंदू हैं। जिन्ना ने मजहबी एजेंडे को मजबूती से थामा।

क्या देश के विभाजन के लिए गांधी और नेहरू भी उतने ही जिम्मेदार थे, जितने जिन्ना?

स्टेनली वॉलपर्ट ने जिन्ना की जीवनी 'जिन्ना ऑफ पाकिस्तान' के अनुसार माउंटबेटन को गांधी जी ने जिन्ना को सरकार गठित करने का पहला मौका देने की बात कही। बीबीसी में किताब के हवाले से प्रकाशित किए गए संदर्भ के अनुसार गांधी ने माउंटबेटन के सामने जिन्ना को सरकार गठिक करने का पहला मौके दिए जाने की बात कही। अगर वह ये प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो कांग्रेस ईमानदारी से खुल कर उनसे सहयोग की गारंटी दे बशर्ते जिन्ना की मंत्रिपरिषद भारतीय जनता के हित में काम करे। माउंटबेटन इस प्रस्ताव को देखकर चौंक गए। माउंटबेटन ने गांधी से पूछा कि इस पेशकश पर जिन्ना क्या कहेंगे? गांधी का जवाब था कि अगर आप उन्हें बताएंगे कि ये फॉमूर्ला मैंने तैयार किया है तो उनका जवाब होगा 'उस धूर्त गांधी ने। बहरहाल, गांधी की ये पेशकश जिन्ना को कभी बताई ही नहीं गई। हां, लेकिन ये जरूर है कि माउंटबेटन ने इस मसले पर नेहरू से बात जरूर की थी। लेकिन नेहरू की प्रतिक्रिया इसको लेकर पूरी तरह नकारात्मक थी।

स्टेनली वॉलपर्ट की किताब के अनुसार नेहरू को ये जानकर बड़ी ठेस लगी कि उनके महात्मा उनकी जगह कायद-ए-आजम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। गांधी जिन्ना को अच्छी तरह से समझते थे। वो जानते थे कि इस तरह का प्रस्ताव जिन्ना के अहम को कितना मीठा स्पर्श दे सकता है। लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि ये सुझाव एकदम अव्यावहारिक है।

78 साल बाद भी हिंदू मुस्लिम एक नहीं वाली थ्योरी पर अटका पाकिस्तान

15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पर नई दिल्ली में रात के 12:00 बजे दस्तखत किए थे कई सदियों बाद भारत को आजादी मिली लेकिन बंटवारे के तौर पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी भारत की छाती पर खींची लकीर से दूसरी तरफ एक नया मुल्क पाकिस्तान बन गया देश के दो टुकड़े हो गए शुरूआती 2 साल तक पाकिस्तान में 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाया गया लेकिन फिर इसे बदलकर 14 अगस्त कर दिया गया । लाशों के ढेर पर मुल्क का बंटवारा और पाकिस्तान के कायद-ए-आजम बनने की सनक पाले जिन्ना ने पाकिस्तान तो बना दिया। लेकिन इसके बाद भी दो राष्ट्र सिद्धांत पर बना उनका मुल्क आज भी वहीं अटका पड़ा है। पाकिस्तान के जनरल हिन्दू और मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाला जहरीला बयान देते हैं। टू स्टेट थ्योरी की बात को 78 साल बाद भी दोहराते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों का मानना था कि हम हर तरह से हिंदुओं से अलग हैं। हमारा मजहब, रिवाज, परंपरा, सोच और मकसद सब अलग हैं। ये टू स्टेट सिद्धांत का आधार है। हम एक नहीं, बल्कि दो राष्ट्र हैं। मुनीर के इस विषैले और सांप्रदायिक बयान के बाद ही पहलगाम में आतंकवादियों धर्म पूछकर पर्यटकों का नरसंहार किया था।

भारत समृद्धि के नए आयाम लिख रहा, पाक बना आतंक का अड्डा

एक साथ आजाद हुए दोनों देशों के बीच वर्तमान समय में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरफ भारत जो समृद्धि के नए आयाम लिख रहा है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। वहीं, पाकिस्तान आतंक का अड्डा बना हुआ है। भारत की इकोनॉमी से जुड़ी तीन रिपोर्ट आईं। तीनों में इस बात के लिए भारत की सराहना की गई है कि ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता के बावजूद इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक रिपोर्ट में भारत की विकास दर का अनुमान भी बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी पर भी आई है, जिसमें बताया गया है कि उसकी ग्रोथ रेट लक्ष्य से बहुत पीछे है। भारत की तुलना में पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आधी भी नहीं है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। विश्व बैंक के 2024 के आंकड़े को देखें तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 3.88 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था (केवल 0.37 ट्रिलियन डॉलर) के आकार से 10 गुना अधिक है।अर्थव्यवस्था के सभी पैमानों पर भारत अपने पड़ोसी पाकिस्तान से मीलों आगे है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 688 अरब डॉलर पर है। वहीं, पाकिस्तान के पास केवल 15 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और आर्थिक पतन की कगार पर है।

दास्तां भारत-पाकिस्तान के विभाजन की : भारत के हाथ से ऐसे छिटका लाहौर

यह एक ऐसे राज्य की कहानी बताएंगे जिसे भारत पाकिस्तान के विभाजन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है और तलवार भुजा ने हमेशा भारत को विषैले तत्वों से बचाया है और समय-समय पर भारत को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त पंजाब को सबसे ज्यादा असर झेलना पड़ा था। वर्ष 1947 में विभाजन के कारण मानव जाति के इतिहास में सबसे विनाशकारी विस्थापनों में से एक देखा गया। बंटवारे के दौरान भड़के दंगे और हिंसा में लाखों लोगों की जान चली गई। ऐसी भीषण त्रासदी थी, जिसमें करीब बीस लाख लोग मारे गए और डेढ़ करोड़ लोगों का पलायन हुआ था। किसी दौर में पंजाब का बार्डर अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करता था। लेकिन विभाजन के बाद पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा ही हमारे पास रहा है। भारत के पंजाब प्रान्त को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया।

पंजाब विभाजन से पहले

पुराने वक्त में पंजाब के काफ अलग अलग नाम थे। जिनमें एक सप्तसिंधु था। जिसका अनुवाद 'सात नदियों की भूमि' है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास हैं जिन्हें भारत में सबसे पवित्र माना जाता है। बंटवारे से पहले पंजाब में 29 जिले थे। उनमें से 16 पाकिस्तान को मिले। बाकी 13 बचे भारत को मिले। 29 जिले अंबाला, जांलधर, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान यानी पांच डिवीजन में बंटे हुए थे। हरेक डिलीजन में छह छह जिले थे। जबकि जालंधर में पांच जिले आते थे। बंटवारे के बाद लाहौर के दो जिले अमृतसर और गुरदासपुर भारत को मिला था।

कैसे धर्म के आधार पर बंट गया पंजाब

3 जून 1947 को विभाजन की मंजूरी मिल गई थी। वहीं, 15 अगस्त को सत्ता हस्तांतरण किया जाना था। भारत को आजाद करने और नया राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए ब्रिटिश बेचैन थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि यह दोनों काम जल्द से जल्द निपटाया जाए। वहीं, पंडित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी चाहते थे कि दोनों देश का जल्द से जल्द बंटवारा हो। पंजाब की स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। वहां से रोज सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही थीं। बंगाल की हालत भी कोई अलग नहीं थी। कई रियासतों ने विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। बड़े पैमाने पर पंजाब और सिंध के इलाकों से भारत की ओर पलायन से



खाद्यान्न की हालत बहुत खराब थी।

लाहौर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बन सका?

एक ऐसा सच है कि वो अगर सही में सच हो जाता तो भारत और पाकिस्तान का नक्शा ही अलग अलग होता। आज अमृतसर पाकिस्तान में होता। सोचिए कि गोल्डन टेंपल के दर्शन के लिए आपको पाकिस्तान की इजाजत लेनी पड़ती। वहीं लाहौर की गलियों में हिंदुस्तानी घूमा करते। क्योंकि लाहौर भारत की झोली में आता। इतना ही नहीं पंजाब के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान में चले जाते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत और पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग करवाया। लेकिन जब धर्म के नाम पर भारत के विभाजन की बात हो रही थी तो उस वक्त सभी दिग्गज जानकार का मानना था कि ये लाहौर भारत के हिस्से में ही आएगा। आज लाहौर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी है। करांची के बाद लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। लाहौर एक ऐसा शहर है जिसका अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। दरअसल, 17 अगस्त 1947 को आजादी मिले दो दिन हो चुके थे। लेकिन करोड़ों लोग हैरान और परेशान थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनका घर, शहर, मुहल्ला भारत में है या फिर पाकिस्तान में है। इसी दिन दोपहर 2 बजे रेड क्लिप लाइन का ऐलान हुआ यानी दो मुल्कों को बांटने वाली विभाजन रेखा। भारत और पाकिस्तान को बांटने वाली लाइन खिची जाती इससे पहले ही पाकिस्तान ने अमृतसर, फिरदौसपुर और गुरदासपुर पर अपना दावा कर रखा था। वहीं सबको लग रहा था कि लाहौर तो भारत का था ही। क्योंकि लाहौर में ज्यादातर आबादी सिखों और हिंदुओं की थी। लेकिन रेड क्लिप साहब के एक ख्याल ने उसे पाकिस्तान को दे दिया।

भारत से बिल्कुल भी अंजान रेड क्लिफ ने खींच दी लकीरें

जब लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहा गया कि आपको एक मुल्क को दो हिस्सों में बांटना है। एक में हिंदू बहुल आबादी रहेगी और दूसरे में मुस्लिम बहुल आबादी रहेगी। माउंटबेटन ने ये काम अपने दोस्त रेडक्लिप को सौंप दी। सर सिरील रेडक्लिफ को भारत का मैप दिया गया और कहा गया कि अगले 10 से 12 दिनों में वो इस काम को कर डाले। कई शहर पाकिस्तान को दिए गए और कई को लेकर क्या तर्क दिए गए वो भी काफी रोचक हैं। भारत से बिल्कुल भी अंजान पेशे से वकील सिरील रेडक्लिफ ने बंटवारे की लकीरें खींचनी शुरू कर दी। यही कारण रहा कि बंटवारे के दौरान ऐसी कई गलतियां हुई कि कई स्थान इधर से उधर हो गए। फिर बंटवारे के बाद लाखों लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। कहा जाता है कि रेडक्लिप खुद अपने काम से खुश नहीं थे। भारत से वापस लंदन जाने के बाद विभाजन से जुड़े सारे दस्तावेज और नक्शे को उन्होंने जला दिया था। बाद में भी उन्होंने इस मसले को लेकर ज्यादा बातें कभी नहीं की।

सीमा निर्धारण में रेडक्लिफ की मनमानी

कमीशन के सामने पंजाब और बंगाल के विभाजन का मुख्य आधार धार्मिक जनसंख्या थी। पंजाब में सिख आबादी और उनके तीर्थ स्थल पूरे पंजाब में फैले हुए थे। उनकी मांग थी कि उनके सारे तीर्थ स्थल भारत के हिस्से में आने वाले पूर्वी पंजाब में शामिल किए जाएं। उधर लीग की ओर से तत्कालीन पंजाब के अम्बाला डिवीजन के पांच जिलों अम्बाला,करनाल, रोहतक, हिसार को छोड़कर शेष पंजाब की मांग थी। रेडक्लिफ का फैसला चौंकाने वाला था। लाहौर में हिदू-सिख आबादी का बहुमत था लेकिन वह पाकिस्तान के हिस्से में गया। लाहौर को पाकिस्तान को दिए जाने का आधार रेडकिल्फ के ही शब्दों में मैंने पहले लाहौर हिंदुस्तान को दे दिया था। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुसलमानों को पंजाब में कोई बड़ा शहर देना होगा, क्योंकि उनके पास राजधानी नही थी।

शिक्षा है विकास की बुनियाद

विजय गर्ग

पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गरीब छात्रों के लिए निजी मेडिकल कालेजों में लागू 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना' को संवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के गरीब छात्रों को मुफ्त शिक्षा दिलाना असंवैधानिक या अनुचित नहीं है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा में सहायता के लिए 'मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना' की शुरूआत की थी। इसमें सरकारी एवं निजी मेडिकल, इंजीनियरिंग और ला कालेज में प्रवेश के पश्चात सौ फीसद फीस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही पुस्तकों, हास्टल फीस और अन्य शैक्षणिक खर्चों में भी मदद की जाती है।

शिक्षा किसी भी देश विकास की बुनियादी तैयार करती है। फिर चाहे वह प्राथमिक शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, इनका उद्देश्य देश और समाज के लिए बेहतर नागरिक तैयार करना होता है। इसी कारण शिक्षा को संविधान में मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर अनेक परिवार ऐसे भी होते हैं, जिनके लिए अपने बच्चों को महंगी होती जा रही शिक्षा दिलाना एक सपने जैसा होता है। गरीबी में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफार्म और आवश्यक सामान खरीदने में कठिनाई होती है। गरीबी कारण बच्चों को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, जिससे उनके सीखने की क्षमता प्रभावित होती है।

गरीब परिवारों को अपने बच्चों की शिक्षा के बजाय उनकी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। केवल भारत में 23.4 करोड़ लोग गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अगर दुनिया में गरीबी है तो उसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा ही है। अगर गरीबी के कारण किसी बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। गरीब छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

समाज के गरीब, कमजोर वर्गों को शिक्षा देने से देश में बेरोजगारी, निम्न आय और इससे संबंधित कई समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षण शुल्क समय पर जमा नहीं करने के कारण सरकारी योजनाओं को असंवैधानिक और अनुचित बताना कहीं से भी उचित नहीं है। जब सरकार गरीब छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए कई योजनाएं ला रही है, तो निजी संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे भी शिक्षण शुल्क के लिए सरकार पर दबाव बनाने के बजाय धैर्य रखें और इस फैसले में उसका साथ दें, ताकि गरीब छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो सके।

मलोट पंजाब

बच्चों के साथ महिलाएं मांग रहीं भीख

▸ भिक्षावृत्ति पर रोक के बाद भी यात्रा मार्ग और धाम में दिख रहे हैं भीख मांगने वाले

▸ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सत्यापन अभियान पर उठ रहे हैं सवाल

उत्तरकाशी। देश और राज्य में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह प्रतिबंध होने के बावजूद गंगोत्री और जनपद मुख्यालय में दिन प्रतिदिन भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ रही है। वहीं गंगोत्री में छोटे-छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भीख मांग रही हैं। साथ ही इनके पास आईडी और आधार कार्ड नहीं होने के कारण इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है।

चारधाम यात्रा शुरू होते ही पिछले कुछ वर्षों से जनपद मुख्यालय सहित गंगोत्री धाम में भीख मांगने और हिमालयी क्षेत्रों के दुर्लभ सामानों के नाम पर नकली सामान बेचने वालों की संख्या बढ़ जाती है। यह लोग गंगोत्री धाम सहित जनपद मुख्यालय में विश्वनाथ मंदिर और कोतवाली के आसपास भीख मांगते हैं, लेकिन इन पर पुलिस सहित एलआईयू और जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं इन लोगों के पास किसी प्रकार के पहचान पत्र और आधार कार्ड नहीं होते हैं।

यह पुलिस के सत्यापन अभियान पर बड़ा सवाल खड़े करते हैं। साथ ही यह अंतरराष्ट्रीय सीमा सुरक्षा की संवेदनशीलता पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न है। गंगोत्री होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि धाम में बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भीख मांग रहे हैं। वहीं पापड़गाड से लेकर गंगोत्री धाम तक पार्किंग, जंगलों में रहने वाले लोगों की वास्तविकता को लेकर पुलिस सहित नगर पंचायत, प्रशासन के पास कोई जानकारी नहीं है। ये लोग कहां से आते हैं और उसके बाद कहां जाते हैं इसकी कोई अधिकारिक जानकारी नहीं है।

वहीं पुलिस मात्र उन्हीं लोगों के सत्यापन तक सीमित है, जिनके पास आधार और आईडी कार्ड है। उसके अलावा भीख मांगने और नकली सामान बेचने वालों की जानकारी किसी के पास नहीं है। ऐसी स्थिति में देश और धामों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता बरत रहे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

एसपी सरिता डोबाल का कहना है कि लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं भीख मांगने और यात्रा में सामान बेचने वाले लोगों की दोबारा जांच करवाई जाएगी।

वार्षिकोत्सव में बिखेरे संस्कृति के रंग

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज के वार्षिकोत्सव नेबुला के पांचवें दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इसमें चिकित्सा छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बृहस्पतिवार को स-स्कृतिक संध्या में विद्यार्थियों ने कुमाऊंनी, गढ़वाली और हिंदी गीतों पर मनमोहक नृत्य कर दर्शकों का मन मोहा। इस दौरान छात्रों ने उत्तराखंड के लोक नृत्यों, शास्त्रीय भारतीय संगीत और अन्य क्षेत्रीय कला की प्रस्तुति दी।

आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी आठ से

अल्मोड़ा। मल्ला महल में शनिवार से आठ जून तक आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी लगेगी। भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड) के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रीति टोलिया ने बताया कि इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जनजातीय उद्यमी भाग लेंगे। प्रदर्शनी में लकड़ी व पत्थर की कलाकृतिया, पयरोग्राफी, वन धन व कृषि आधारित वस्तुएं, साज-सज्जा सामग्री जैसे हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कार्यशाला के माध्यम से दी गई नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी

उत्तरकाशी/मोरी। विश्व तंबाकू दिवस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं राजकीय महा विद्यालय मोरी में गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्वनाथ स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ सीएमओ डॉ. बीएस रावत ने किया। उन्होंने छात्राओं को तंबाकू के दुष्परिणाम एवं कोटपा अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। प्राचार्य जगदीश प्रसाद सेमवाल ने कहा कि नशा मुक्त करने के लिए युवाओं को आगे आकर उत्साह से भाग लेना चाहिए। आचार्य अनिल बहुगुणा ने सभी छात्राओं को नशे से दूर रहने की अपील की। काउंसलर शशि बाला ने युव-ाओं को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर जिला अस्पताल में सिविल जज श्वेता राणा चौहान ने कर्मचारियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। उधर, राजकीय महा विद्यालय मोरी में आयोजित गोष्ठी में छात्राओं को नशे से दूर रहने की अपील की।

नकली कस्तूरी और शेर के पंजों के नाम पर ठगे जा रहे चारधाम यात्री

उत्तर काशी। चारधाम यात्रा के दौरान गंगोत्री से लेकर यमुनोत्री धाम नकली कस्तूरी, शेर के पंजे, शिलाजीत की जमकर अवैध बिक्री हो रही है, लेकिन वन विभाग और जिला प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इनको बेचने वाले लोग स्वयं को उत्तराखंड और नेपाल का निवासी बताकर चारधाम यात्रियों को गुमराह कर इनकी बिक्री कर रहे हैं।

चारधाम यात्रा शुरू होते ही गंगोत्री सहित जनपद मुख्यालय और यमुनोत्री धाम के आसपास एक बड़े समुदाय की भीड़ एकत्रित हो जाती है। यह मुख्य पार्किंग सहित मंदिरों और मुख्य पड़ावों के आसपास बैठकर नकली कस्तूरी, शेर के पंजे, शिलाजीत, रुद्राक्ष आदि बेचते हैं। इसमें ये लोग कस्तूरी को उच्च हिमालयी क्षेत्रों से लाया हुआ बताते हैं और उस नकली कस्तूरी पर इत्र डालकर यात्रियों को गुमराह करते हैं।

वहीं एक मुखी से लेकर पंचमुखी रुद्राक्ष के नाम पर यात्रियों से धोखाधड़ी की जाती है। स्थानीय निवासी सतेंद्र सेमवाल का कहना है कि ये लोग महाराष्ट्र, हरिद्वार, हैदराबाद आदि जगहों से आकर यहां पर अपने आप को स्थानीय निवासी बताते हैं। वहीं स्थालिक राम और रुद्राक्ष और शिलाजीत आदि का यात्रियों को बताया जाता है कि यह नेपाल से लाया गया है। इससे प्रदेश और इन दुर्लभ जड़ी-बूटियों, पेड़, जीव जंतुओं की अस्मिता पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन और वन विभाग की ओर से इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और यात्रियों के साथ इसके नाम पर लूट हो रही है। डीएफओ डीपी बलूनी का कहना है कि ये लोग नकली सामान बेचते हैं। इस संबंध में समय-समय पर इन लोगों पर कार्रवाई की जाती है।



चिन्यालीसौड़ और खरादी में निकाली तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा



बड़कोट/चिन्यालीसौड़। भाजपा ने ग्रामीण मंडल चिन्यालीसौड़ और खरादी में कालिंदी मंडल ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की तीनों सेनाओं की वीरता पर तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। साथ ही तिरंगा शौर्य यात्रा निकालकर भारत की एकता और अखंडता का संदेश दिया। गत बुधवार को बड़ी संख्या में भाजपाई खरादी बाजार में तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिक, भाजपाई और ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। मंडल अध्यक्ष प्रवीन सिंह असवाल और महंत केशव गिरी महाराज के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंडल अध्यक्ष प्रवीन असवाल ने कहा कि सेना के शौर्य के सम्मान में व ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है।

नए वेरिएंट का भारत में तहलका

नोएडा। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से फिर से दस्तक दे दी है जिसकी वजह से नोएडा कोरोना से दहशतज़दा हैं। बताया जाता है कि नोएडा में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। गत गुरुवार को 24 घंटों में 19 नए केस दर्ज किए गए है। जिससे जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। इनमें 22 महिलाएं और 21 पुरुष शामिल हैं। सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और मरीजों की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है।

यूपी में कोविड मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 59 पहुंच गई है।

प्रदेश में कोरोना से जान गंवाले वाले लोगों की संख्या 2 हो गई है। भारत में मिले कोरोना के दो नए वेरिएंट एनबी.1.8.1 और एलएफ-7 ओमिक्रॉन के ही सब-वैरिएंट हैं, जो 2022 तक सक्रिय था. एनबी.1.8.1, जेएन.1 वैरिएंट का ही वंशज है जबकि एलएफ-7 इससे संबंधित एक अन्य सब-वैरिएंट है। ये वैरिएंट वायरस के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन लेकर आते हैं, जो इसे मनुष्यों में आसानी से फैलने में मदद करते हैं।

एनबी.1.8.1 और एलएफ-7 ओमिक्रॉन के ही सब-वैरिएंट

एनबी.1.8.1 और एलएफ-7ओमिक्रॉन के ही सब-वैरिएंट हैं, जो 2022 तक सक्रिय था. एनबी-1.8.1, जेएन 1 वैरिएंट का ही वंशज है। जबकि एलएफ-7 इससे संबंधित एक अन्य सब-वैरिएंट है. ये वैरिएंट वायरस के स्पाइक प्रोटीन में कई म्यूटेशन लेकर आते हैं, जो इसे मनुष्यों में आसानी से फैलने में मदद करते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रारंभिक आकलन एनबी.1.8.1 वैरिएंट को स्वास्थ्य के लिए कम जोखिम वाला मानता है। हालांकि, इसके स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन - ए435एस, वी 445एच और टी478आई।

अन्य वैरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक हैं और इम्युनिटी को बायपास करने क्षमता का रखते हैं। दुनिया भर में, एनबी.1.8.1 का पता एशिया, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया सहित 20 से अधिक देशों में लगाया गया है।

शैक्षिक गुणवत्ता से बच सकती है भारतीय संस्कृति

ऋषिकेश। आदर्शनगर स्थित जातीराम अग्रवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित प्रधानाचार्य अभ्यास वर्ग के तीसरे दिन भी जारी रहा। बीते गुरुवार को शिशु शिक्षा समिति के प्रांत प्रदेश निरीक्षक डॉ. विजयपाल सिंह ने प्रतिभाग किया। उन्होंने विद्यालय विकास में प्रधानाचार्य की भूमिका पर चर्चा करते हुए बताया कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसमें भारत की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा, आज हमारी संस्कृति कम होती जा रही है। हमें शैक्षिक गुणवत्ता और नए क्रियाकलापों से भारत की संस्कृति को बचाना होगा।

अत्याधुनिक कृषि तकनीकी से परिचित हुई महिलाएं

रुद्रपुर। जिला मुख्यालय के एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर में जलवायु आधारित कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिला कृषकों को सशक्त किया गया। इसमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करते हुए समूह की महिलाओं को जलवायु अनुकूल कृषि की आधुनिक तकनीकों और पद्धतियों से प्रशिक्षित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान गत दिनों शुक्रवार को प्रशिक्षक अंकित बालियान ने बताया कि जैसे-जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे-वैसे खेती के तरीके भी बदलने की जरूरत है। इसमें समूह की महिलाओं कृषकों की कृषि उपज और उससे होने वाली आमदनी में निरंतर वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा, जिससे परिवारों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

दो आईआरएस ऐसे भिड़े, एक हॉस्पिटलाइज्ड

▸ सरकारी कार्य में बाधा डालने का लगाया आरोप

▸ आयकर भवन बना दो आईआरएस अधिकारियों के बीच मारपीट का गवाह

▸ हाथापाई से बचाव के दौरान उनकी अंगूठी गौरव के होंठ में लग गई।

▸ गौरव की तहरीर पर मामला हुआ दर्ज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का आयकर भवन गुरुवार की शाम दो आईआरएस अधिकारियों के बीच मारपीट का गवाह बना। हजरतगंज के नरही स्थित आयकर भवन में दो आ-ईआरएस ऐसे भिड़े कि एक को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। दरअसल, उनके सिर में गहरी चोट आई है। आरोप संयुक्त आयकर आयुक्त योगेंद्र मिश्रा पर लगा है। आरोप है कि उन्होंने उन्होंने हाथापाई के दौरान मुख्यालय डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग पर गिलास फेंक मारा। इससे उनके सिर पर चोट आई और होंठ कट गया। उन पर पेपरवेट भी फेंककर मारने का आरोप लगा है। आयकर उपायुक्त की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में संयुक्त आयुक्त योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

क्या है विवाद की वजह?

संयुक्त आयुक्त योगेंद्र मिश्रा का मामले में बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हमने एक आरटी-आई में पूछा था कि हमारे तबादले की वजह क्या है? उनका आरोप है कि उपायुक्त गौरव गर्ग ने संवेदनशील मामले को लीक किया था। मुख्यालय में रहते हुए आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे थे। संयुक्त आयुक्त का कहना है कि गुरुवार को सीनियर अफसर के सामने गौरव गर्ग से कहा कि आरटीआई का जवाब तो दे दीजिए। इस पर गौरव गर्ग ने अपील में जाने की बात कही।

बकौल योगेंद्र मिश्रा इसी मुद्दे पर दोनों अधिकारियों के बीच बहस शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। आईआरएस गौरव गर्ग की पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी हैं। वह लखनऊ में डीसीपी इंटेलीजेंस के पद पर तैनात हैं। इससे मामला हाई प्रोफाइल हो गया है।

क्रिकेट मैच का आया मामला

हजरतगंज कोतवाली में ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। बीएनएस की धारा 109, 121, 221, 324, 352, 351 धारा 2 एवं 3 के तहत केस दर्ज किया गया है। घायल डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग की तहरीर पर पुलिस ने गुरुवार देर रात यह कार्रवाई की। इस पूरे मामले में फरवरी 2025 के क्रिकेट मैच का मामला भी सामने आया है। दरअसल, गौरव गर्ग के आरोप पर केस दर्ज किया गया है। उनका कहना है कि फरवरी 2025 में बीबीडी क्रिकेट ग्राउंड पर क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ था।

आरोप के अनुसार, संयुक्त आयुक्त योगेंद्र कुमार मिश्रा ने विभागीय मैच के दौरान क्रिकेट खेलने और कप्तान बनाने का दबाव बनाया था। इसको लेकर जमकर हंगामा मचाया था।

फाइनल मैच के दौरान वे पिच पर लेट कर हंगामा करने लगे थे। विरोध किए, जाने पर साथी खिलाड़ी अधिकारियों और टीम के सदस्यों को गालियां थीं। मामले का विभाग ने संज्ञान लिया। विभागीय कार्रवाई करते हुए योगेंद्र मिश्रा का उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया।

मामले की जांच को लेकर योगेंद्र मिश्रा गुरुवार को आयकर कार्यालय पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने उपायुक्त गौरव गर्ग के साथ बुरी तरह मारपीट की। एफआईआर में गौरव गर्ग का बड़ा आरोप लगाया कि पहले गिलास से चेहरे पर हमला किया गया। इसके बाद मेरा गला दबाया गया। योगेंद्र मिश्रा पर अपने जूते से गौरव गर्ग के प्राइवेट पार्ट पर हमला करने की बात भी सामने आई है। हजरतगंज पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दफ्तर में मचा हड़कंप

दरअसल, 2016 बैच के आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग गुरुवार की शाम आयकर भवन में छठे तल पर स्थित प्रमुख आयकर आयुक्त स्तर के अधिकारी के कमरे में बैठे थे। वहां पर 2014 बैच के आईआर-एस संयुक्त आयुक्त योगेंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वहां उपस्थित थे। आरट-ीआई के मसले को लेकर गौरव गर्ग और योगेंद्र मिश्रा में बहस शुरू हुई। आयकर भवन में यह बहस देखते ही देखते पहले कहासुनी और फिर मारपीट में बदल गई। सीनियर अफसर जब तक दोनों को छुड़ाते, दोनों भिड़ चुके थे।

आरोप है कि संयुक्त आयुक्त ने गौरव गर्ग पर पानी से भरा ग्लास दे मारा। हाथापाई के दौरान उनकी अंगूठी गौरव गर्ग के चेहरे पर लग गई। हंगामा मच गया। कर्मचारी भागते हुए कमरे में पहुंचे। गौरव गर्ग के चेहरे, सिर और हाथ पर चोट लगी थी।

तत्काल पहुंचाया गया अस्पताल

गौरव गर्ग को तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं, इस मामले में योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि गौरव गर्ग ने पहले अपशब्द कहे थे। इसके बाद थप्पड़ मार दिया। हाथापाई से बचाव के दौरान उनकी अंगूठी गौरव के होंठ में लग गई। इस मामले में अब गौरव गर्ग की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। एसीपी हजरतगंज विकास जायसवाल का कहना है कि गौरव गर्ग ने जानलेवा हमला और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

क्रेम मावजिम्बुइन गुफा में एक अनोखी मछली

मेघालय, असम। भारत के मेघालय राज्य में एक जूलॉजिस्ट ने दो साल पहले एक अनोखी मछली देखी। अब रिसर्चर्स ने इसे एक नई प्रजाति बताया है। यह मछली जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह रह सकती है जो इसे गुफा में रहने वाली अन्य मछलियों से अलग बनाती है।

एक अनोखी मछली

जूलॉजिस्ट खुर बैनह मखिम ने मेघालय के खासी हिल्स में क्रेम मावजिम्बुइन गुफा में एक अनोखी मछली देखी। इस मछली का रंग पीला-हरा है और इसके मुंह के पास लंबी मूंछ जैसी संरचनाएं हैं। सबसे खास बात इस मछली की आंखें हैं। आमतौर पर गुफा में रहने वाली मछलियां अंधेरे में रहने के कारण आंखें खो देती हैं, लेकिन यह मछली अलग है।

पूंछ पर मोटी काली धारी

शिस्ट्रा डेन्फिक्लावा नामक इस मछली की पूंछ पर मोटी काली धारी है। शोधार्थियों का कहना है कि-यह मछली गुफा के 60 मीटर गहरे पानी के गड्ढे और पास की सतह की धारा में रहती है।

यह खोज जर्नल ऑफ फिश बायोलॉजी में प्रकाशित एक शोध आलेख के आधार पर प्रोफेसर दंदाधर शर्मा ने कहा कि गुफा का माहौल बहुत कठिन है। वहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और पानी में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, फिर भी यह मछली गुफा और सतह दोनों जगह जीवित रह सकती है।

मेघालय में 1,500 से 1,700 चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की गुफाएं हैं, जिनमें से कई का अभी तक पता नहीं चला. ये गुफाएं जटिल हैं और जंगलों में बनी हैं, जिससे इन तक पहुंचना मुश्किल है. पिछले पांच सालों में, रिसर्चर्स ने इन गुफाओं में नई मछली प्रजातियों की खोज की है. 2019 में, टीम ने नियोलाइसोचिलस प्यार नाम की दुनिया की सबसे बड़ी गुफा मछली खोजी थी.



मछलियों की खासियत

गुफा में रहने वाली मछलियां अंधेरे, ठहरे हुए पानी और कम ऑक्सीजन में जीवित रहती हैं। इनके पास आंखें नहीं होतीं, क्योंकि अंधेरे में रंग या दृष्टि की जरूरत नहीं होती। इनकी स्वाद और गंध की क्षमता तेज होती है। ये गुफा में मौजूद पत्तियों, समुद्री जीवों या चमगादड़ के मल से भोजन लेती हैं। हैरानी की बात है कि इनकी संतानें आंखों के साथ पैदा होती हैं, लेकिन बड़े होने पर आंखें खो देती हैं।

नर्सिंग कॉलेज में भारी लापरवाही उजागर, प्रैक्टिकल के अंकों में गड़बड़ी से पूरा बैच ही हो गया फेल



अलवर । अलवर में बहरोड़ रोड पर सुरंग के निकट स्थित संवर्धन नर्सिंग कॉलेज में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही ने 39 छात्र-छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा दिया। कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल घोषित कर दिया गया। इसका कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा अंकों की गलत गणना बताई जा रही है। प्रैक्टिकल के लिए 50 में से अंक भेजने थे, लेकिन इन्हें 25 में से समझकर भेज दिया गया। इस गंभीर भूल ने पूरे बैच को फेल कर दिया, जिससे छात्रों और उनके परिवारों में गहरा आक्रोश और चिंता है। कॉलेज प्रशासन इसे मानवीय भूल करार दे रहा है, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित है कि स्टूडेंट्स का खराब हुआ एक साल कैसे वापस आएगा।

प्रैक्टिकल अंकों में हुई गंभीर चूक

संवर्धन नर्सिंग कॉलेज के सेकंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर के 39 स्टूडेंट्स उस समय स्तब्ध रह गए, जब उनकी मार्कशीट में प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल होने की जानकारी मिली। जांच करने पर पता चला कि कॉलेज प्रशासन ने प्रैक्टिकल के अंकों को 50 के बजाय 25 में से गणना कर भेजा था। प्रिंसिपल दिवाकर शर्मा ने इस गलती को स्वीकार करते हुए इसे कॉलेज स्टाफ की मानवीय भूल बताया। उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट्स के अंक 25 से कम होने के कारण उन्हें फेल घोषित कर दिया गया, जबकि अंकों की गणना 50 के आधार पर होनी चाहिए थी। इस लापरवाही ने पूरे बैच को गंभीर संकट में डाल दिया।

स्टूडेंट्स और परिवारों में आक्रोश

इस घटना ने कॉलेज के स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। हालांकि स्टूडेंट्स ने मीडिया के सामने खुलकर बोलने से परहेज किया, लेकिन फोन पर कई छात्रों ने अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि अन्य सभी विषयों में उनके अंक अच्छे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में फेल होने की वजह से उनका एक साल बर्बाद होने का खतरा है। खास बात यह है कि प्रैक्टिकल की पूरी प्रक्रिया कॉलेज में ही हुई थी और अंक भी यहीं से भेजे गए थे। इस गलती ने न केवल कॉलेज प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य को भी अनिश्चितता में डाल दिया। परिवारवाले भी इस स्थिति से चिंतित और परेशान हैं।

कॉलेज प्रशासन की चुप्पी

कॉलेज प्रशासन ने इस मामले को मानवीय भूल बताकर अपनी जिम्मेदारी कम करने की कोशिश की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि स्टूडेंट्स के खराब हुए साल की भरपाई कैसे होगी। स्टूडेंट्स ने इस लापरवाही के लिए कॉलेज प्रशासन के साथ-साथ संबंधित विभाग के अधिकारियों की भी शिकायत की है। उनकी मांग है कि इस गलती को तुरंत सुधारा जाए और उन्हें पास किया जाए। हालांकि न तो कोई स्टूडेंट इस मुद्दे पर खुलकर सामने आ रहा है, और न ही कॉलेज प्रशासन इस मामले में कोई ठोस जवाब दे रहा है। इस चुप्पी ने स्टूडेंट्स के बीच और अधिक असंतोष पैदा कर दिया।



ब्राजील में बोले केंद्रीय मंत्री शेखावत

'भारत ने विकास के साथ संस्कृति को भी प्राथमिकता दी'

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत ने विकास और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलने का रास्ता चुना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक तरक्की के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा होनी चाहिए।

शेखावत ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सभी ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) के साथ मिलकर काम करने को पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत ने यह दिखाया है कि संस्कृति को भी सतत विकास के केंद्र में रखा जा सकता है। भारत सिर्फ आर्थिक नहीं, नैतिक एआई, डिजिटल सुरक्षा और पारंपरिक ज्ञान के जरिए पर्यावरण की रक्षा जैसे मुद्दों पर भी काम कर रहा है। सांस्कृतिक धरोहर की चोरी और अवैध ऑनलाइन व्यापार पर भी चिंता जताई। उन्होंने ब्राजील द्वारा इसे रोकने की कोशिशों की सराहना की।

शेखावत ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक भारत ने 642 सांस्कृतिक धरोहर वस्तुएं वापस मंगवाई हैं, जो देश की स्मृति, सम्मान और विश्वसनीयता की बहाली का काम करती हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये हमारे इतिहास और संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें सभ्यताओं और संस्कृति के स्तर पर भी वैश्विक नेतृत्व करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे सांस्कृतिक वातावरण की बात की जो विविधता का सम्मान करे, मानवता को मजबूत बनाए और साझा मूल्यों को बढ़ावा दे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग विषयक कार्यशाला

ऋषिकेश। पं. ललित मोहन शर्मा श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि आज का युग तकनीकी नवाचारों का युग है। एआई और एमएल अब केवल शोध या विज्ञान की अवधारणाएं नहीं रहीं, बल्कि ये हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनती जा रही हैं। स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट सिटी तक, हर जगह इन तकनीकों की उपयोगिता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बीते बुधवार को आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन कुलपति प्रो. एनके जोशी ने किया। कार्यशाला में उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से आए विशेषज्ञ मोहित कुमार और एल्ड्रिन मेनन ने विचार प्रस्तुत किए। कार्यशाला में छात्र छात्राओं के लिए एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सत्र भी आयोजित किया गया।

नारी शक्ति की प्रतीक थीं अहिल्याबाई होल्कर : वंदना

शाहपुर/रैत(कांगड़ा)। पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला कांगड़ा की ओर से शाहपुर के रैत में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अहिल्याबाई होल्कर के महान योगदान, उनके जीवन मूल्यों और समाज सेवा में उनके अमूल्य कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस संगोष्ठी में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी, कांगड़ा के विधायक पवन काजल, प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु, भाजपा जिलाध्यक्ष सचिन शर्मा व पूर्व मंत्री सरवीण चौधरी और मंडल अध्यक्ष अशोक वशिष्ठ सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को अहिल्याबाई होल्कर के प्रेरणादायी जीवन से अवगत कराना और महिलाओं को उनके पदचिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित करना रहा। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि भाजपा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों को सच्ची श्रद्धांजलि देती है। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होल्कर नारी शक्ति की प्रतीक थीं, जिन्होंने शासन, धर्म, समाज सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए। कार्यक्रम का समापन अहिल्याबाई होल्कर को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया।

नेरना पंचायत के वार्ड तीन में पेयजल को तरसे लोग

राजा का तालाब (कांगड़ा)। जल शक्ति विभाग उपमंडल राजा का तालाब के तहत ग्राम पंचायत नेरना के वार्ड तीन के लोग बीते पांच दिनों से पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानीय लोग इस विषय में शुक्रवार को नेरना स्थित जलशक्ति विभाग के कार्यालय में अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और मांग पत्र सौंपा। स्थानीय लोगों शकुंतला देवी, बीना देवी, रेनू कुमारी, आशा देवी, बिमला देवी, पूजा, निशा, रितिका, अरुण, रवि कुमार, रोहित, बल्ली का कहना है कि पांच दिन से उनको पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। इस समस्या के बारे में विभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। लोगों का कहना है कि अगर समस्या का समाधान एक दो दिन में नहीं किया जाता है तो स्थानीय विधायक से मिलेंगे। इस विषय में जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता अमित रंधावा का कहना है कि बुधवार से नलकूप की मोटर खराब है। मोटर को रिपेयर के लिए भेजा गया है। समस्या को देखते हुए लोगों को ओवरहेड टैंक से सप्लाई दी जा रही है। मोटर ठीक होते ही नलकूप से सुचारु रूप से सप्लाई शुरू कर दी जाएगी।

मनाई गई हिंदी पत्रकारिता दिवस की 199वीं वर्षगांठ, सम्मानित हुईं विभूतियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रेमचंद सभागार में हिंदी पत्रकारिता की 199वीं वर्षगांठ मनाई गई। अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ और रंगभारती संस्था के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान देने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अंग्रेजों ने हिंदी पत्रकारिता को कुचलने का काम किया था। ऐसे विकट समय में भी हिंदी पत्रकारिता की अलख जगाए रखने वाले पत्रकारों ने अपनी लेखनी से भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। रंगभारती के अध्यक्ष श्याम कुमार ने बताया कि पंडित युगल किशोर शुक्ल ने 30 मई, 1826 को कोलकाता में प्रथम हिंदी समाचारपत्र ह्यउदंत मार्तण्डह्न का प्रकाशन किया था। संचालन अनीता सहगल ने किया। विशिष्ट अतिथि मनकामेश्वर मंदिर की महंत देव्यागिरी रहीं।

इनका हुआ सम्मान-बाबूराव विष्णु पराड़कर रंगभारती सम्मान - ओमप्रकाश पांडेय। लक्ष्मीनारायण गर्दे सम्मान - नरेंद्र भदौरिया व रामसागर। रामकृष्ण खाडिलकर सम्मान - रामदत्त त्रिपाठी। सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय सम्मान - विजय शंकर पंकज, दिनेश गर्ग एवं अनिल भारद्वाज। गणेशशंकर विद्यार्थी सम्मान - सुरेंद्र दुबे, कन्हैयाबख्श सिंह व प्रमोद गोस्वामी। डॉ. धर्मवीर भारती सम्मान - प्रणय विक्रम सिंह व आशीष मिश्र। शंकरदयालु श्रीवास्तव सम्मान - घनश्याम दुबे व शेखर पंडित। हेरम्ब मिश्र सम्मान - सर्वेश सिंह, जयप्रकाश त्यागी व अनिल कुमार। कृष्णबिहारी श्रीवास्तव सम्मान - सिद्धार्थ सौरभ, शिशुपाल सिंह व विनय कृष्ण रस्तोगी। अमीर खुसरो सम्मान - सिदरत अंसारी। न्यायमूर्ति प्रेमशंकर गुप्त सम्मान- न्यायमूर्ति डॉ. शेखर यादव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। प्रयागराज दिव्य महाकुंभ सम्मान- महाकुंभ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद के अलावा पर्यटन, जलशक्ति, परिवहन, खाद्य-रसद व नागरिक आपूर्ति विभाग को।

वर्तमान सरकार और सुशासन पर भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन



इंदौर। पुण्यश्लोका माता देवी अहिल्या के त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बाल विनय मंदिर में देवी अहिल्या का सुशासन एवं वर्तमान सरकार की समानता विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरूआत भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष मेहता ने की।

निर्णायक की भूमिका में रहे राजीव छालानी, विनीता धर्म और संगीता भरुका। अतिथियों ने मां अहिल्या के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रखर वक्ता रहे स्व. उमेश शर्मा को भी पुष्पांजलि अर्पित की।

भाषण का महत्व

इस अवसर पर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें वक्तव्यकला को लेकर जानकारी दी। मिश्रा ने कहा कि जब हम भाषण दें तब हमें आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। साथ ही जिस विषय पर हम बोल रहे हैं उस विषय की अधिक से अधिक जानकारी हमें होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी बॉडी लैंग्वेज में भी आत्मविश्वास दिखना चाहिए।

यह रहे विजेता

भाषण प्रतियोगिता में 42 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिसमें प्रथम पुरस्कार प्रशांत तीसरी, द्वितीय पुरस्कार पवित्र प्रजापति, तृतीय पुरस्कार मोहित सुनेरी तथा सात प्रोत्साहन पुरस्कार शैलेंद्र चौहान, वंशिका डाबी, तोशी राजोरिया, भरत उदावत, लिना लोदवाल, धरम रायकवार एवं सुहानी महकाम को मिले। कार्यक्रम का संचालन नेहा शर्मा ने तथा आभार वृंदा गौड ने व्यक्त किया।

जोधा और अकबर के विवाह को लेकर नया विवाद

यह विवाह ऐतिहासिक नहीं, बल्कि झूठ पर आधारित एक कहानी: हरिभाऊ बांगड़े

उदयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एक कार्यक्रम के दौरान दिए अपने बयान में इतिहास की पुस्तकों में दर्ज जोधा और अकबर के विवाह को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह विवाह ऐतिहासिक नहीं, बल्कि झूठ पर आधारित एक कहानी है, जिसे ब्रिटिश इतिहासकारों के प्रभाव में भारतीय इतिहास में दर्ज किया गया। बुधवार शाम उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि जोधा और अकबर की शादी हुई थी। उस पर फिल्म भी बनी और किताबों में भी लिखा गया, लेकिन यह झूठ है। अकबरनामा में इस विवाह का कोई जिक्र नहीं है।



राज्यपाल बागड़े ने यह भी दावा किया कि आमेर के शासक भारमल ने अकबर से अपनी दासी की बेटी का विवाह कराया था, न कि अपनी राजकुमारी जोधा का। उन्होंने ब्रिटिश लेखन पर सवाल उठाते हुए कहा कि औपनिवेशिक इतिहासकारों के प्रभाव के कारण भारतीय इतिहास में कई तथ्य तोड़े मरोड़े गए और झूठी कहानियां प्रचारित की गईं। बागड़े के इस बयान ने 1569 में मुगल सम्राट अकबर और आमेर के राजा भारमल की पुत्री के बीच हुए ऐतिहासिक विवाह को लेकर फिर से बहस छेड़ दी है। आमेर, जो अब जयपुर के पास स्थित है, लंबे समय तक कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा है। बाद में सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में राजधानी को जयपुर स्थानांतरित कर दिया था।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीय शूरवीरों के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनका लिखा हुआ इतिहास ही लंबे समय तक सच मान लिया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाद में जिन भारतीयों ने इतिहास लिखा, वे भी अंग्रेजों के दृष्टिकोण से प्रभावित थे।

राज्यपाल बागड़े ने विशेष तौर पर मुगल सम्राट अकबर और राजपूत वीर महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप द्वारा अकबर को संधि की चिट्ठी भेजने का दावा पूरी तरह भ्रामक है। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप ने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। इतिहास में अकबर के बारे में अधिक और महाराणा प्रताप के बारे में बहुत कम पढ़ाया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे हर क्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को देशभक्ति और वीरता का प्रतीक बताते हुए कहा कि यदि ये दोनों महानायक एक ही कालखंड में होते, तो भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता।

उन्होंने कहा, दोनों के जन्म के बीच 90 साल का अंतर था, लेकिन दोनों को समान रूप से देशभक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बागड़े ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में महाराणा प्रताप की एक भव्य घुड़सवार प्रतिमा स्थापित की गई है, जो उनके सम्मान का प्रतीक है।

राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में

जयपुर। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। इस बार आरोप सीधे कुलपति अल्पना कटेजा पर लगे हैं, जिन पर वित्तीय, प्रशासनिक और अकादमिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रों और विपक्षी नेताओं की शिकायतों के आधार पर राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए जयपुर के संभागीय आयुक्त को पत्र लिखा है। राज्यपाल को मिली शिकायतों में कहा गया है कि वर्ष 2021-22 में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीच प्रक्रिया में नई अधिसूचना जारी कर साक्षात्कार के नियमों में बदलाव कर दिया, जो यूजीसी के निर्धारित मानकों के विरुद्ध था। छात्रों ने इसे शैक्षणिक धोखाधड़ी करार दिया और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

छात्रों की ओर से तीन अप्रैल को राज्यपाल को एक पत्र सौंपा गया था, जिसमें विश्वविद्यालय में व्याप्त वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की शिकायत की गई थी। इसके बाद 16 अप्रैल को विपक्ष के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने भी इसी मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल को पत्र भेजा और तत्काल जांच की मांग की।

नस्ल सुधार की दिशा में पशुपालन विभाग की नई पहल

देसी बकरियों से तैयार होगी बीटल और जमनापरी नस्ल

धर्मशाला, कांगड़ा। कांगड़ा जिले में देसी बकरियों की नस्ल सुधार की दिशा में पशुपालन विभाग ने एक नई पहल की है। अब पशुपालकों को देसी बकरियों के जरिये बीटल और जमनापरी नस्ल की उन्नत बकरियां पालने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जिले के 11 पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भधारण के लिए विशेष टीके उपलब्ध करवा दिए हैं। इन नस्लों की बकरियां अधिक दूध देती हैं और इनका वजन भी अधिक होता है, जिससे पशुपालकों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। पशुपालन विभाग द्वारा पहले चरण में नगरोटा बगवां में पांच बकरियों को ये टीके परीक्षण के रूप में लगाए गए, जो सफल रहे। अब बड़ोह, सद्दूं, जवाली और नूरपुर में यह मुहिम शुरू की है।

25 रुपये होगा प्रति बकरी का कृत्रिम गभार्धान



संबंधित क्षेत्रों के 11 चिकित्सालयों के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया है। टीकों की अगली खेप पशुपालकों की मांग के अनुसार ढाई महीने बाद टीके मंगवाए जाएंगे। यह आपूर्ति मथुरा केंद्र से आएगी।
डॉ. सीमा गुलेरिया,
उपनिदेशक, पशुपालन विभाग कांगड़ा

पशुपालन विभाग के अनुसार एक बकरी का कृत्रिम गभार्धान महज 25 रुपये में किया जाएगा। इससे पैदा होने वाली बकरियों का वजन 30 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि स्थानीय देसी नस्लों का वजन अधिकतर 15 से 20 किलोग्राम ही होता है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भी यह नस्लें फायदेमंद हैं। ये बकरियां प्रति दिन 1.5 से 2 लीटर तक दूध देती हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार बकरी पालन आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए त्वरित आय का माध्यम बन सकता है।

जब भी जरूरत हो, किसान बकरी बेचकर नकद आय अर्जित कर सकते हैं। कम लागत, सरल देखरेख और तेज लाभ इसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए सुलभ स्वरोजगार बनाता है।

गुट्टे या किट्ठु





यह पारंपरिक खेल बच्चों और बड़े दोनों द्वारा खेला जाता है। इस साधारण खेल के लिए 5 छोटे पत्थरों की आवश्यकता होती है। आप हवा में एक पत्थर उछालते हैं और उस पत्थर के जमीन पर गिरने से पहले अन्य पत्थरों को चुनते हैं। यह गेम कितने भी लोगों के साथ खेला जा सकता है।

क्या गुनाहगार आजाद घूमते रहेंगे'

सीजफायर पर आश्चर्य की बड़ी वजह यह भी है कि सीज फायर की पुष्टि के दिन सुबह ही विदेश सचिव ने पेस ब्रीफिंग में' बताया गया था कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात कर रहा है। और भारतीय सशस्त्र बल अलर्ट पर है विदेश सचिव ने जो जानकारी दी उसका लब्बोलुआब यही था कि दोनों देश पूर्णकालिक युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुके हैं फिर ऐसा क्या हुआ कि भारत युद्ध विराम के लिए राजी हो गया। क्या इतिहास फिर अपने आपको दोहरा रहा है। 1912 में भी हमने यही किया था। हमारे बहादुर सिपाहियों ने युद्ध के मैदान में खून बहाकर जो कुछ प्राप्त किया था। उसे हमने समझौते की टेबल पर लौटा दिया। पांच दशक के बाद फिर वही दोहरा बैठेंहैं क्या? हालांकि भारत की सैन्य कार्रवाई सीमित और सुनियोजित थी जिसका उद्देश्य आतंकी संगठन के इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना था। पाकिस्तान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत हर बार यही कहता रहा कि उसका हमला सिर्फ आतंकी ठिकानों पर है। सैन्य प्रतिष्ठान, या नागरिक संस्थानों या सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना नहीं है लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने सीमा क्षेत्र का उल्लंघन को माना और भारत के सरहदी क्षेत्रों में रिहायशी इलाकों गोलाबारी की। इसके बाद भारत ने पलटवार किया जिसमें वह पूरी तरह से सफल भी हुआ। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान केबीच छिड़ा संघर्ष लगभग-लगभग वास्तविक युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुका था जिस तरह से दोनो देशों देश एक दूसरे पर पलटवार कर रहे थे। उससे साफ था कि दोनों के बीच शुरू हुई जंग वास्तविक युद्ध में बदल सकती है। लेकिन इस बीच भारत-पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर आई जिससे हर कोई भौंचक्का रह गया। सीजफायर की खबर पर लोग विश्वास करने को तैयार नहीं थे। हालां-कि, सीजफायर की घोषणा के तीन घंटे बाद ही पाकिस्तान की ओर से उसके उल्लंघन की घटनाएं सामने आने लगीं।श्री नगर में ड्रोन अटैक, अमृतसर में रेड अलर्ट और सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर में ब्लैक आउट की घोषणा किया गया। सवाल है कि संघर्ष में बहुत बेहतर स्थिति में होने के बावजूद भारत युद्ध विराम के लिए राजी क्यों हो गया। सैन्य क्षमता, वैश्विक रेस्पांस, ग्राउंड पोजिशन सब कुछ तो भारत के पक्ष में था। फिर भी भारत बिना शर्त सीजफायर के लिए तैयार हो गया। दिल्ली पर मिसाइल दागने का झूठा दुस्साहस पाकिस्तान ने किया। इसके बावजूद युद्धविराम समझौते के लिए राजी होना क्या भारत की सामरिक कमजोरी तो नहीं दिखाता। कोई स्थाई सामरिक था रानीतिक लाभ हासिल किए बिना सीजफायर पर सहमत हो जाना कहीं' भारत की सामरिक चूक तो नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की मध्यस्थता (मैं तो हस्हीतक्षेप ही मानूंगा के बाद भारत युद्ध विराम के लिए राजी हुआ। के क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ विवाद की सूरत में किसी तीसरे पक्ष के दखल को स्वीकार कर लिया है। क्या भारत की विदेश नीति में यह बड़ा बदलाव है। दूसरा - क्या भारत के इस कदम को 1942 के शिमला समझौते का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। तृतीय अगर कुछ देर के लिए मान भी लिगा जाए कि क्या भारत ने अमेरिकी हस्तक्षेप के चलते संघर्ष विराम को स्वीकार किया है। तो क्या अमेरिका ने भारत को इस बात की गारंटी दी है कि पाकिस्तान भविष्य में आपनी सरजमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं करेगा। दुनिया पहले ही रूस-युक्रेन युद्ध देख चुकी है और इसराइल-फिलिस्तीन संघर्ष में उलझी है। भारत और पाकिस्तान, दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। दोनों के बीच अगर संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है अथवा दक्षिण एशिया में लंबी लड़ाई होती हैं तो यह न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक अस्थिरता का कारण बन सकती थी। हालांकि, सीजफायर से पहले खबरें आई थीं कि भारत अनेक बाद के खिलाफ अपनी नीति में बड़ा परिवर्तन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर 0.2 के दौरान भारत ने आतंकवाद के खिलाफ नीति में साफ कर दिया कि-भविष्य में भारत पर किया गया कोई हमला-आतंकी हमला एक्ट आफ वार माना जाएगा। अब पाकिस्तान इस बहुत गहरे तक अपने मन में बैठा ले कि सीजफायर की वजह से एक बारगी तो भारत के खौफ से बच गया है, लेकिन भविष्य में दुःसाहस करता है तो उसके विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की जा सकती है। अब तक भारत आतंकवाद को लेकर सावधानी बातचीत और संयम के रास्ते चलता रहा है लेकिन अब देश के भीतर होने वाली किसी भी आतंकवादी घटना में पुलिस और जांच एजेंसियों की औपचारिकता का इंतजार किए बिया सीधे कार्रवाई कर सकेगा। कुल मिलाकर कहें तो अब आतंक की घटना को युद्ध समझा जाएगा और सॉफ्ट स्टेट की छवि से बाहर निकल कर रिएक्ट करेगा। हालांकि भारत के अप्रत्याशित संघर्ष विराम पर जो प्रश्न उठ रहे है। उसको उठाया जाना अनुचित नहीं है लेकिन सैन्य झड़पों और छिटपुट घटनाओं को बड़े संघर्षों में बदलने से रोकने में सीजफायर कारगर कदम भी हो सकता है। इतिहास में ऐसे उदाहरण कम नहीं है। जहां संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच सीजफायर के स्थाई शांति बहाली का रास्ता खोलने का काम किया है। संघर्ष विराम की शर्तें और उसका रूप क्या होगा यह तो आनेवाला समय-दिन ही बतयेगा लेकिन पहलगाम के गुनाहगारों का क्या होगा? क्या इन्हें यूं ही स्वतंत्र रूप से घूमते रहने दिया जाएगा या उनकी पहचान करने और पकड़ने की कोशिश जारी रहेगी। लाख टके का यह सवाल है. जिसका उत्तर आना अभी बाकी है।

> भारत के विदेश सचिव विकास मिसरी ने जिस आनन फानन में युद्ध विराम समझौते की मीडिया के सामने पुष्टि की उसपर भी सवाल खड़े किये जा सकते हैं। मिसरी ने अपने दो लाइन के के वक्तव्य में इतना ही कहा है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया उनके बीच सहमत बनी कि दोनों पंक्ष जमीन हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य गतिविधि बंद कर देंगे। मिश्री ने यह वक्तव्य अंग्रेजी भाषा में दिया। वक्तव्य के बाद वह पत्रकारों के सवाल लिए बिना चले गए। यहां तक कि उन्होंने अपने वक्तव्य का हिंदी में अनुवाद भी नहीं किया जबकि सामान्य तौर पर अंग्रेजी में दी गई जानकारी को बाद में हिंदी में अनुदित किए जाने की परंपरा है।

कलम की बेटियाँ: आवाजें जो कुचली नहीं जा सकतीं

जब कोई स्त्री कलम उठाती है, तो वह केवल शब्द नहीं रचती—वह एक युग को चुनौती देती है। पत्रकारिता के रणक्षेत्र में जब महिलाएं उतरती हैं, तो उनके पास केवल पत्रकारिता की दक्षता नहीं होती, बल्कि उस समाज से भी लड़ने का हौसला होता है जो हर सवाल करने वाली स्त्री को अपराधी समझता है। महिला पत्रकारों की यह लड़ाई दोहरी होती है – एक सच के लिए, और दूसरी अपने अस्तित्व के लिए।



पत्रकारिता में महिलाओं की भूमिका बढ़ता लेकिन अस्वीकारा गया कद

स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता की कहानी में महिलाओं ने अपने पैर जमाए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में उनके संघर्ष और योगदान को अक्सर वह सम्मान और स्थान नहीं मिला जो उनके पुरुष समकक्षों को सहजता से मिलता है।

हर मुल्क की पत्रकारिता का इतिहास महिला पत्रकारों की साहसिक कहानियों से भरा हुआ है। भारत में हर्षा भोगले, राणा अय्यूब, मृणाल पांडे, और न केवल नामचीन बल्कि अनगिनत अनसुनी आवाजों ने जमीनी स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक अपनी पहचान बनाई है।

लेकिन इन सफलताओं के पीछे छिपा है एक कठोर सच – मीडिया हाउसों में महिला पत्रकारों की हिस्सेदारी कम है, उन्हें निर्णायक पदों तक पहुँचने से रोका जाता है, और उनकी रिपोर्टिंग को भावनात्मक या ह्यकमजोरह्व बताकर अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

दोहरी चुनौतियाँ: पेशेगत और लैंगिक

पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण पेशा है। खबर के लिए चौकसी, सत्यापन, त्वरित संपादन, और कभी-कभी खतरनाक परिस्थितियों में जाकर रिपोर्टिंग करना होता है। महिलाओं के लिए यह चुनौती दोगुनी हो जाती है।

मीडिया के पुरुष वर्चस्व वाले माहौल में महिला पत्रकारों को अक्सर ह्यग्लैमरह्व या ह्यलाइफस्टाइलह्व रिपोर्टिंग तक सीमित कर दिया जाता है। फील्ड रिपोर्टिंग से दूर रखना, नेतृत्व वाली भूमिकाओं से वंचित करना, और ह्यजोखिम उनके लिए नहीं हैह्व जैसी पितृसत्तात्मक धारणा उनकी योग्यता को कमतर आंकती है।

कई बार उन्हें अपने परिवार और पेशे के बीच भी संतुलन बनाना पड़ता है, जो पुरुष पत्रकारों की अपेक्षा महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है।

डिजिटल पत्रकारिता में भयावहता की पराकाष्ठा

तकनीकी प्रगति ने पत्रकारिता के स्वरूप को बदल दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने खबरें और आवाजें तेजी से पहुँचाने का अवसर दिया, लेकिन साथ ही इसने ऑनलाइन उत्पीड़न के नए रूप भी जन्म दिए हैं।

महिला पत्रकारों को व्यक्तिगत हमलों, घृणास्पद टिप्पणियों, ट्रोलिंग, और रेप की धमकियों का सामना करना पड़ता है। उनके चरित्र पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, उन्हें ह्यदेशद्रोहीह्व, ह्यरंडीह्व, या 'बिकी हुई' कहकर अपमानित किया जाता है। यह केवल व्यक्तिगत हमले नहीं हैं – यह लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की आजादी पर हमले हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं को निशाना बनाना उनके सच बोलने के अधिकार को दबाने का एक माध्यम बन गया है।

व्यक्तिगत संघर्ष और उदाहरण

राणा अय्यूब की कहानी इस जद्दोजहद की सबसे खतरनाक मिसाल है। उनकी खोजी पत्रकारिता ने सत्ता के कई काले पक्षों को उजागर किया, लेकिन इसके एवज में उन्हें बलात्कार और हत्या की धमकियाँ मिलीं।

गौरी लंकेश की निर्भीक लेखनी ने भी सत्ता की पोल खोल दी, लेकिन इसी के कारण उनकी हत्या कर दी गई। यह घटनाएं संकेत देती हैं कि यदि कोई महिला पत्रकार सत्ता के खिलाफ आवाज उठाए, तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है।

सामाजिक संरचना और पितृसत्ता की साज़िश

जब कोई महिला पत्रकार सत्ताधारियों या सामाजिक अन्याय पर सवाल करती है, तो उसे ह्यविद्रोहीह्व या ह्यचरित्रहीनह्व कहकर तिरस्कृत किया जाता है। इसके विपरीत, पुरुष पत्रकारों को उनकी निडरता और साहस के लिए सराहा जाता है। यह दोहरा मापदंड महिला पत्रकारों के मनोबल को तोड़ने और उन्हें चुप कराने की रणनीति का हिस्सा है। समाज को यह समझना होगा कि सवाल करना स्त्री की स्वतंत्रता का भी अधिकार है, और महिला पत्रकार केवल ह्यसूचनाएं देने वालीह्व नहीं, बल्कि ह्यसच्चाई की खोज करने वालीह्व हैं।

संगठनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ

पत्रकार संगठनों और मीडिया हाउसों में महिला पत्रकारों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रवैया दुर्लभ है। जब कोई महिला उत्पीड़न की शिकायत करती है, तो उसे ह्यटीम की खराब सदस्यह्व या ह्यअनुशासनहीनह्व कहा जाता है। उसे आलोचना और बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इससे कई महिला पत्रकार आवाज दबाने को मजबूर होती हैं। यह एक गम्भीर समस्या है, क्योंकि मीडिया का आधार ही सच और निष्पक्षता है, लेकिन जब महिला पत्रकारों की आवाज दबाई जाती है, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर पड़ती हैं।

बदलाव की मशाल: उम्मीद की किरणें

फिर भी, इस अंधेरे के बीच कई महिला पत्रकार डटी हुई हैं। वे हार नहीं मानतीं, बल्कि और जोर से सत्ता से सवाल करती हैं।

मृणाल पांडे, बरखा दत्त, सुप्रिया शर्मा जैसी नामी महिला पत्रकारों ने साबित किया है कि कलम की ताकत जेंडर से नहीं मापी जाती। वे युवा पत्रकाराओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। कई संगठन और मंच अब महिला पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा, और सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। यह बदलाव धीरे-धीरे मीडिया जगत को समावेशी और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

समाधान और आवश्यक पहल

न्यूजरूम में लैंगिक समानताः संपादकीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। नेतृत्व के पदों पर महिला पत्रकारों को अधिक मौका दिया जाए।

सख्त साइबर सुरक्षा कानूनः डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिला पत्रकारों के खिलाफ हमलों को रोकने के लिए कड़े कानून लागू किए जाएं और उनका प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षाः महिला पत्रकारों के लिए अलग हेल्पलाइन, कानूनी सहायता और काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।

सामाजिक जागरूकताः महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह और पितृसत्तात्मक सोच को दूर करने के लिए समाज में शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

लोकतंत्र की परिभाषा में विस्तारः अभिव्यक्ति की आजादी को स्त्री के संदर्भ में पुनः परिभाषित किया जाए, ताकि महिला पत्रकारों को बिना भय के अपना काम करने की स्वतंत्रता मिले।

महिला पत्रकार केवल खबर नहीं देतीं, वे एक नई चेतना लिखती हैं – वह चेतना जो सत्ता की आँखों में आँखें डालती है, जो समाज की खामोशी को तोड़ती है, और जो लोकतंत्र की सच्ची प्रहरी बनती है। उनकी अनदेखी, उत्पीड़न और चरित्रहनन केवल महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। अब समय आ गया है कि हम उनके संघर्ष को देखें, सराहें और उसके लिए खड़े हों। क्योंकि जब स्त्रियाँ कलम उठाती हैं, तो सिर्फ स्याही नहीं बहती – एक युग बदलने की शुरूआत होती है।



-प्रियंका सौरभ

हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति में 'चौपाल' सिर्फ एक बैठने की जगह नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और कभी-कभी राजनीतिक निर्णयों का अनौपचारिक मंच रही है। यह जगह जहाँ बुजुर्ग अपनी ताश की गड्डी के साथ बैठते हैं, वहीं यह सामाजिक आचार-संहिताओं का अनकहा विधान भी तय करती है। लेकिन समय के साथ सवाल यह उठने लगा है कि क्या यह चौपालें लोकतंत्र की संवैधानिकता से ऊपर होती जा रही हैं?

हरियाणा में चौपालों का वर्चस्व : लोकतंत्र की जड़ें या परंपरा की जंजीर?

हरियाणा के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में चौपाल महज एक बैठने की जगह नहीं, बल्कि एक परंपरा, एक सत्ता संरचना, और एक अनौपचारिक न्याय प्रणाली रही है। पीपल के पेड़ के नीचे या पक्के चबूतरे पर बैठकर जब गाँव के बुजुर्ग चर्चा करते हैं, तो उसे आम भाषा में ₹चौपाल₹ कहा जाता है। पर यह चौपाल सिर्फ बतकही तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक दिशा तय करने वाली संस्था बन गई है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह वर्चस्व सकारात्मक है या फिर यह लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज के रास्ते में रोड़ा बन रहा है?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः चौपालों की भूमिका

हरियाणा में जब पंचायतें पूरी तरह विकसित नहीं हुई थीं, तब चौपालों का महत्व और अधिक था। गाँव का कोई भी मामला झ जमीन का झगड़ा हो, विवाह संबंध तय करना हो या किसी के बहिष्कार का निर्णय झ सब चौपाल में होता था। यह स्थानीय स्वशासन का प्रतीक था, जो सामूहिक संवाद के सिद्धांत पर टिका था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, लोकतंत्र की संस्थाएं, पंचायत चुनाव, पुलिस-प्रशासन और अदालतें सशक्त हुईं, वैसे-वैसे चौपालों की भूमिका को भी बदल जाना चाहिए था। परंतु हरियाणा में आज भी चौपालें सामाजिक फैसलों की ₹अनौपचारिक अदालत₹ बनी हुई हैं।

चौपाल बनाम संविधानः एक टकराव

भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है झ जाति, लिंग, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। वहीं चौपालों में अक्सर फैसले जातिगत पदानुक्रम पर आधारित होते हैं। जैसे किः ₹इस जाति के लड़के को उस जाति की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए।₹ ₹उसने पंचायत के बिना शादी की है, इसलिए उसका बहिष्कार होगा।₹ ये निर्णय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हैं। खासकर महिलाओं और दलितों को चौपाल में बोलने का अवसर कम ही मिलता है। अधिकतर मामलों में चौपालें पितृसत्ता और जातिवाद का किला बन जाती हैं।

सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक शोषण?

चौपालें कभी-कभी ऐसे सामाजिक नियंत्रण की भूमिका निभाती हैं जो कानून से पहले कार्रवाई करता है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई लड़की मोबाइल फोन इस्तेमाल करती है, तो चौपाल का फैसला आता है झ ₹मोबाइल पर प्रतिबंध लगाओ।₹ या फिर ₹लव मैरिज करने वालों को गाँव से निकाल दो।₹ ऐसे फैसले सामाजिक शोषण की श्रेणी में आते हैं। आज भी हरियाणा में ऑनर किलिंग की घटनाएं सामने आती हैं, जिनकी जड़ें चौपाल के फैसलों में होती हैं। इस वर्चस्व का मूलभूत कारण यह है कि चौपालें अक्सर बुजुर्ग पुरुषों के एकाधिकार में होती हैं, जहाँ युवा, महिलाएं या सामाजिक रूप से हाशिए पर खड़े लोग आवाज नहीं उठा सकते।

चौपालों की सकारात्मक भूमिका भी है?

यह कहना गलत होगा कि चौपालें केवल नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। कुछ क्षेत्रों में चौपालें आपसी विवाद सुलझाने, सामाजिक समरसता बनाए रखने, और सामूहिक फैसले लेने का लोकतांत्रिक रूप भी हैं। जैसेः जल संरक्षण, नशामुक्ति अभियान, या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास। विवाहों में फिजूलखर्ची रोकने के लिए नियम बनाना। लेकिन यह भूमिका तब तक रचनात्मक है, जब तक वह सबकी भागीदारी सुनिश्चित करे और संविधान के अनुरूप हो।

राजनीतिक उपयोग और दुरुपयोग

हरियाणा की राजनीति में चौपालों का बड़ा उपयोग हुआ है। नेता चौपालों में जाकर जनसंपर्क करते हैं, लेकिन साथ ही जातिगत गोलबंदी और सामाजिक ध्रुवीकरण का जरिया भी इन्हें बनाते हैं। पंचायत चुनावों में या विधानसभा चुनावों में ₹चौधरी जी का फैसला सब पर भारी₹ जैसी धारणाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुँचाती हैं।

महिलाएं और चौपालः प्रवेश वर्जित?

हरियाणा की चौपालों में महिलाओं की सहभागिता आज भी अत्यंत सीमित है। भले ही ग्राम पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन जब वही महिला सरपंच चौपाल में अपनी बात रखने जाती है, तो उसे चुप करा दिया जाता है।

यह दोहरा मापदंड है - कागजी सशक्तिकरण और जमीनी उपेक्षा

महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को चौपाल संस्कृति से सीधा विरोध मिला है। इसीलिए चौपालों का वर्चस्व महिलाओं की भागीदारी के लिए बाधक बनता जा रहा है।

नई पीढ़ी की सोच और चौपालों से दूरी

आज की युवा पीढ़ी, जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और शहरी जीवन से प्रभावित है, चौपाल संस्कृति से खुद को काटती जा रही है। उन्हें यह प्रणाली पुरानी और पक्षपाती लगती है। युवा सवाल पूछते हैंः मैं किससे प्यार करूं, इसका फैसला कोई बुजुर्ग कैसे करेगा? मेरे करियर का रास्ता मैं तय करूंगा, चौपाल नहीं।₹ इस पीढ़ी की लोकतांत्रिक चेतना चौपालों के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। यही लोकतंत्र की दिशा है, जिसे गाँवों में सशक्त बनाना जरूरी है।

क्या चौपालों का कोई नया स्वरूप हो सकता है?

समाधान यह नहीं है कि चौपालों को पूरी तरह खारिज कर दिया जाए, बल्कि जरूरत है उन्हें पुनर्परिभाषित करने की। उदाहरणस्वरूपः चौपालों में महिलाओं, दलितों, युवाओं को बराबर बोलने का अधिकार मिले। फैसले नियम और कानून की कसौटी पर कसे जाएं। चौपालों का उपयोग सामाजिक अभियानों, ग्रामीण विकास और शिक्षा के प्रचार में हो। अगर चौपालें लोकतंत्र का विस्तार बनें, तो वे आज भी प्रासंगिक रह सकती हैं।

चौपालः परंपरा या पितृसत्ता का प्रतीक?

चौपालों की मूल अवधारणा आपसी संवाद, परामर्श और विवाद निपटारे की रही है। परंतु अब यह जगह कई बार न्याय की बजाय सामाजिक दमन और जातीय वर्चस्व का अड्डा बनती दिखती है। हरियाणा के गांवों में अधिकतर चौपालों पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व होता है। महिलाएं वहाँ न तो बोल सकती हैं, न ही बैठ सकती हैं। यह असमानता सिर्फ लिंग आधारित नहीं है, जातिगत और आर्थिक वर्गों के हिसाब से भी है। पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों की बातों को अनसुना कर देना इन चौपालों की पुरानी रवायतों में शामिल हो चुका है।

आंकड़ों की सच्चाईः

ऑनर किलिंग के मामलों में हरियाणा शीर्ष पर है। 2021 में देश में दर्ज 25 मामलों में से 17 हरियाणा से थे। इन अधिकतर मामलों में खाप या चौपाल की भूमिका रही। रिपोर्ट के अनुसार, 60% ग्रामीण विवाद पहले चौपाल में ही सुलझाए जाते हैं, जिनमें से 80% फैसलों में महिलाएं शामिल नहीं होतीं। हरियाणा राज्य महिला आयोग (2020) की एक रिपोर्ट बताती है कि 72% ग्रामीण महिलाओं को चौपाल की रूढ़िवादी व्यवस्था के कारण अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है।

करनाल ज़िले का ह्यबल्ला गाँवह्व, हिसार ज़िले का नलवा गाँव

वर्ष 2016 में करनाल के बल्ला गाँव की चौपाल ने एक प्रेमी युगल को 'एक ही गोत्र' का हवाला देते हुए गाँव से निकालने का निर्णय लिया। महिला को परिवार से अलग कर दिया गया और लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई। जब यह मामला कोर्ट में गया, तो अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना। लेकिन तब तक समाज ने अपनी 'सजा' सुना दी थी। यह केस यह दशार्ता है कि चौपालें आज भी अपनी परंपरा की आड़ में कानून की अनदेखी कर सकती हैं। 2019 में हिसार के नलवा गाँव की चौपाल में एक दलित परिवार को केवल इसलिए सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी बेटी ने एक सवर्ण युवक से विवाह कर लिया था। पंचायत ने न सिर्फ पूरे परिवार को चौपाल पर आने से रोका, बल्कि गाँव के कुएँ से पानी भरने और राशन की दुकानों से खरीददारी करने पर भी रोक लगा दी।

सकारात्मक मिसालः बीबीपुर गाँव, भिवानी, रेवाड़ी ज़िले का 'ढोसी गाँव'

लेकिन हर चौपाल कट्टरता का प्रतीक नहीं है। भिवानी के बीबीपुर गाँव ने चौपाल की परिभाषा को बदलकर दिखाया। वहाँ के सरपंच सुनिल जगलान ने चौपाल को महिलाओं की आवाज बनाने का मंच बनाया। सेल्फी विद डॉटरह्व अभियान यहीं से शुरू हुआ। चौपाल में महिला मंच स्थापित किया गया, जहाँ महिलाएं भी समान अधिकार से भाग लेती हैं। नशा मुक्ति, बाल विवाह, शिक्षा और शौचालय जैसे मुद्दों पर खुली बहस हुई और निर्णय लिए गए। बीबीपुर की यह चौपाल बताती है कि जब समाज चाहे, तो परंपरा को आधुनिक मूल्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। हरियाणा पंचायत विकास रिपोर्ट (2021) के अनुसार, राज्य के 78% गाँवों में चौपालों को किसी भी कानूनी ढांचे के अंतर्गत संचालित नहीं किया जाता, जिससे वे अक्सर संविधान के दायरे से बाहर होकर निर्णय लेती हैं। गाँव की चौपाल में 2022 में पहली बार युवाओं की मांग पर डिजिटल चौपाल की शुरूआत की गई। इसमें गाँव की समस्याओं को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ब्लॉक कार्यालय से जोड़ा गया और महिलाओं को भी समान रूप से भागीदारी मिली। इसका सीधा प्रभाव यह हुआ कि गाँव में शौचालय निर्माण, छात्रवृत्ति वितरण और मनरेगा की मजदूरी जैसे मुद्दों पर त्वरित निर्णय और समाधान हुए।

मीडिया में चौपालों की आलोचना

ह्वहरियाणा में खाप पंचायतें अब भी सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करती हैं, संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार कर।ह्व ह्वरोहतक के एक गाँव में जींस पहनने पर लड़की को सजा सुनाई गई झ चौपाल ने फैसला सुनाया, महिलाएं निष्कासित थीं।ह्व हरियाणा की चौपालें जहाँ एक ओर संवाद और समुदाय का प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर वे लोकतंत्र और समानता के रास्ते में बाधा भी बन चुकी हैं। इन चौपालों को अब आत्मावलोकन की जरूरत है। उन्हें चाहिए कि वे परंपरा को ढालें, लेकिन समावेशिता, लिंग समानता और संवैधानिक मूल्यों के साथ। बीबीपुर की चौपाल एक आदर्श है, जबकि बल्ला की चौपाल एक चेतावनी। अब यह हरियाणा के गाँवों पर है कि वे किस रास्ते को चुनते हैं—लोकतंत्र की दिशा या परंपरा की परछाईं?

वर्चस्व नहीं, सहभागिता चाहिए

हरियाणा की चौपालें समाज का आईना हैं झ लेकिन जब आईना ही धुंधला हो जाए, तो तस्वीर भी बिगड़ जाती है। चौपालों का वर्चस्व अगर समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाता है, तो उसे चुनौती देना जरूरी है। लेकिन अगर इसे समावेशी, संवेदनशील और लोकतांत्रिक बनाया जाए, तो यह ग्रामीण भारत की सबसे मजबूत संस्था बन सकती है। हमें यह तय करना होगा कि चौपालें संवाद का मंच रहेंगी या सत्ता का सिंहासन? जब तक चौपालें सबकी आवाज नहीं बनतीं, तब तक उनका वर्चस्व लोकतंत्र के लिए खतरा ही रहेगा।

- डॉ. सत्यवान सौरभ

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास लंबे संघर्ष और बदलावों से युक्त

भारतीय सेना में महिला शक्ति का दम दिखाई देने लगा है। पुरुषों की तरह महिलाएं भी सेना में बढ़ चढ़कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रही हैं। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग में सेना की दो महिला अधिकारियों द्वारा युद्ध से संबंधित जानकारी देना एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत के पराक्रम की तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने पेश किया और बताया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कैसे और क्या कार्यवाही की। सेना की दोनों महिला अधिकारियों ने सैनिक कार्यवाही की हर दिन प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से देश दुनिया को ताजा जानकारी प्रदान कर यह दिखा दिया कि भारत में महिला शक्ति भी किसी से कम नहीं है।

भारत में सदियों से महिलाओं को मातृशक्ति का दर्जा दिया जाता रहा है। कहा गया है कि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।।

अर्थातः जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। जहां नारियों की पूजा नहीं होती, वहां किए गए सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। हम देश में साल में दो बार नवरात्र पर मातृशक्ति रूपी मा दुर्गा की पूजा कर देश दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मातृ शक्ति भी किसी से कम नहीं है। अब तो हमारी सेना में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर अपनी उत्कृष्ट क्षमता दिखा दी है। महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही है। तो युद्ध भूमि में हर प्रकार की भूमिका निभाने को तैयार नजर आ रही है।

भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी का इतिहास लंबे संघर्ष और बदलावों से भरा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही महिलाएं भारत की सुरक्षा और सेवा में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देती रही हैं। लेकिन सेना में औपचारिक तौर पर उनकी नियुक्ति का रास्ता बहुत बाद में खुला। साल 1943 में बनी रानी झांसी रेजिमेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का हिस्सा थी। यह पहली बार था जब महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर सक्रिय रूप से दिखाई दी। आजादी के बाद भी सशस्त्र बलों में महिलाओं को लंबे समय तक सहायक भूमिकाओं तक ही सीमित रखा गया।

भारत की तीनों सेनाओ (थल सेना, नौसेना, वायु सेना) में महिलाओं की संख्या को लेकर अगस्त 2023 में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संसद में बताया था कि तीनों सेना में 11414 महिलाएं सेवाएं दे रही है। थल सेवा में 7054 महिलाएं सेवारत है। इनमें 1733 महिला अधिकारी है। यह आंकड़ा 1 जनवरी 2023 तक का है। भारतीय वायु सेवा में 1654 अधिकारी सेवारत है जबकि 155 महिलाएं एयर मेन (अग्निवीर) के रूप में सेवा दे रही है। भारतीय नौसेना में 580 महिलाएं अधिकारी के रूप में सेवारत है जबकि 727 महिलाएं सैलर्स (अग्निवीर) के तौर पर तैनात है।



इसी तरह 1212 महिलाएं भारतीय थल सेना के आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में 168 महिलाएं आर्मी डेंटल कार्स में और 3841 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में कार्यरत है। 151 महिलाएं नौसेना के मेडिकल कॉर्प्स में 10 महिलाएं डेंटल कार्य और 380 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत है। 274 महिलाएं भारतीय वायु सेवा के मेडिकल कॉर्प्स में पांच महिलाएं डेंटल कॉर्प्स में और 425 महिलाएं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सेवारत है।

पहले महिलाओं को शार्ट सर्विस कमीशन में ही लिया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन मिलने लगा है। अब एनडीए की कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटों पर लड़कियां सिलेक्ट होती है और वह भी ओपन कंपटीशन में मुकाबला करके। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मार्च 2025 में संसद में बताया था कि 2022 में महिला कैडेट्स के पहले बैच की एंट्री के बाद से अब तक एनडीए में 126 महिलाओं को एडमिशन मिला है। आर्म्ड फोर्सज में आने के बाद उनके लिए भी अवसर समान होते हैं। उनका करियर प्रोग्रेस वैसा ही होगा जैसा लड़कों का होगा। सर्विस रूट समान होते हैं। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सेना में पूरी तरह जेंडर न्यूट्रलाइजेशन हो गया है।

सेना में आज हमारी महिला कॉम्बैट पायलट भी है। जो मिसाइल चलती है मोर्चे पर भी जाती है। वह इंजीनियरिंग का कार्य भी देखती है और सैटेलाइट को भी नियंत्रित करती है। अब महिलाएं डिफेंस भी करती है। टेक्निकल इंटेलिजेंस भी एकत्रित करती है। अभी तक आमने-सामने की लड़ाई में महिलाओं को नहीं भेजा जाता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले की स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह 2016 में भारतीय वायु सेवा की तेजस फाइटर स्पाइडर में शामिल होने वाली पहली महिला बनी। इससे पहले वह मिग 21 बाइसन फाइटर प्लेन भी उड़ा चुकी है। ग्रुप कैप्टन सालिया धामी वायु सेवा की ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी है जो फ्रंटलाइन काम्पैक्ट यूनिट की कमान संभाल रही है। फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली भी वह पहली महिला अधिकारी है। भारत की सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और थलसेना एवं नौसेना की चिकित्सा सेवाओं का नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं।

रक्षा बलों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की प्रगति धीमी रही है। लेकिन लोगों का मानना है कि इसमें लगातार प्रगति हुई है। अब एक साथ बहुत सारी महिलाएं प्रमुख भूमिकाओं में हैं। वे दूसरों के लिए रास्ता बना रही हैं। उनके प्रदर्शन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वे अच्छा काम कर रही हैं तो उन्हें स्वीकार करना आसान होगा और आने वाली महिलाओं के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाएं केवल 10 या 14 साल तक सेवाएं दे सकती हैं। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाती हैं। लेकिन अब उन्हें स्थायी कमीशन के लिए आवेदन करने का भी मौका मिलेगा। जिससे वो सेना में अपनी सेवाएं आगे भी जारी रख पाएंगी और रैंक के हिसाब से सेवानिवृत्त होंगी। साथ ही उन्हें पेंशन और सभी भत्ते भी मिलेंगे। 1992 में पांच साल के लिये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए महिलाओं का पहला बैच भर्ती हुआ था। इसके बाद इस सर्विस की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। 2006 में शार्ट सर्विस कमीशन को 14 साल कर दिया गया।

भारतीय सेना अब महिलाओं को सशत्र बल में नियुक्ति के लिए उनके लिए तय की गई नीतियों को लागू कर प्रोत्साहित करती है। इसके लिए महिलाओं के लिए आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिटरी नर्सिंग सेवाओं के लिए परमानेंट कमिशन को मंजूरी दी गई है। अब 11 आर्म्स एंड सर्विसेज में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमिशन मिलता है। जिनमें आर्मी सर्विस कोर, आर्मी आर्डनेंस कोर, आर्मी एडुकेशन कोर, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, इंजीनियर कोर, सिगनल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स और मकैनिकल कोर, इंटेलीजेंस कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन, रीमाउंट एंड वेटनरी कोर आदि शामिल हैं। परमानेंट कमिशन के बाद महिला अधिकारी इंडियन आर्मी के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में शामिल आर्टिलरी का हिस्सा बनने लगी है। सेना आर्टिलरी की लगभग 300 रेजिमेंट और लगभग 5,000 अधिकारी हैं। आर्टिलरी में शामिल महिला अधिकारियों की बोफोर्स, होवित्जर, के-9 वज्र जैसी तोपों पर भी 2023 में तैनाती की अनुमति दी जा चुकी है। वर्तमान में भारतीय सशस्त्र बलों में नियुक्तियों में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। पुरुष और महिला जवानों की हथियारों और सेवाओं के लिए तैनाती में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया जाता है। सभी की पोस्टिंग सेना की जरूरतों के अनुसार की जाती है। भारतीय सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमिशन के लिए 23 नवंबर 2021 को एक जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोग्रेशन पॉलिसी लाई गई थी। इसके जरिए महिलाओं को हथियारों व अन्य सेवाओं में समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

आखिर घटिया निर्माण का रहस्य

देश के सबसे लंबे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा जिले के भांडरोज के पास पर भारी वाहन गुजरने से सड़क धंस गई जिससे बड़ा गड्ढा हो गया था। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया है। था। यहां भांडरोज टोल के पास भारी वाहन गुजरने मात्र से सड़क धंस गई है। थी जिससे सड़क के बीचो-बीच 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया था। इस एक्सप्रेस वे पर गड्ढे होने के बाद इसमें भी घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल तथा लापरवाही का आरोप लगाया गया था। इस परियोजना के निर्माण पर लगभग एक लाख करोड़ रुपए की लागत आई थी। 12 फरवरी, 2023 इसका भी उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही उद्घाटन किया था। और अपने संबोधन में इसे देश की आधारभूत संरचना का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया था। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही महीनों में बारिश ने इस उत्कृष्ट निर्माण की वास्तविकता को उजागर कर दिया था। इस तरह के दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो या तो निर्माण के समय ध्वस्त हो गए। या क्षतिग्रस्त होगा। या उद्घाटन के कुछ समय बाद ही इनकी असलियत उजागर हो गई। अभी गत वर्ष बिहार में इस तरह एक के बाद एक कई बड़े पुल ढह गए। गत वर्ष अयोध्या नगरी में कई जगह सड़कें धंस गई। चंडीगढ़ से राजस्थान जाने वाला अंबाला से होकर गुजरने वाला हाईवे अपने निर्माण के कुछ ही समय बाद क्षतिग्रस्त हो गया था। इस पर बने कई पुल भारी वाहन गुजरने पर आज भी थर-थर कांपते हैं। यह सारे गड्ढे विकसित राष्ट्र के मार्ग में पड़ने वाले गड्ढे हैं जिनकी जिम्मेदारी न तो कांग्रेस की है न पंडित नेहरू की। सवाल यह है कि- इस तरह के घटिया निर्माण का रहस्य क्या है? कौन हैं इन कंपनियों के मालिक जो जनता के टैक्स के पैसों की इस तरह खुलकर लूट करते हैं। जन धन की लूट खसोट का यह सिलसिला आखिर कभी खत्म भी होगा। या नहीं। इन लुटेरी निर्माण कंपनियों को किसकी शह मिली हुई है? क्या वजह है कि जिन जुगलों को विदेशी आक्रांता बताकर दिन रात वोट बटोरने की राजनीति की जाती है। उनके समय के बनाए हुए हजारों निर्माण आज भी पूरी मजबूती से, साथ आज सिर बुलंद किये खड़े हैं। इसी तरह अंग्रेजों के शासन काल के अनेक महत्वपूर्ण निर्माण आज तक क्षतिग्रस्त नहीं हुए। उदाहरणार्थ- 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटित ब्रिटिश वास्तुकारों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किये गये पुराने संसद भवन का आज तक बाल भी लोका नहीं हुआ जबकि सेंट्रल विस्ता परियोजना के अंतर्गत बना नया संसद भवन जिसका उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। उसमें पहली बारिश के दौरान पानी टपकने लगा था। निश्चित रूप से यह इस भवन की गुणवत्ता या निर्माण में कमी के कारण ही था इस नये संसद भवन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। पहुंचो थी। परंतु आश्चर्य है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस व विकास का हर वक्त ढिंढोरा पीटने वाली सरकार को विकास कहीं गड्ढों में घुसा जा रहा है तो कहीं आंधी में उड़ा जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर को गत दिनों तेज आंधी, बारिश व तूफान का सामना करना पड़ा। इस तेज आंधी में बड़े दिल्ली स्टेशन के करीब नबी करीम क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान की दीवार गिर गई जिसमें दब जाने से तीन लोगों की मौत हो गई। और तीन लोग घायल हो गए जबकि कई जगहों पर पेड़ उखड़ने का भी समाचार है। परन्तु शायद इस आंधी का सबसे अधिक प्रकोप न्यू अशोक नगर रैपिड मेट्रो स्टेशन को झेलना पड़ा। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत आने वाले इस स्टेशन के एक बड़े हिस्से की छत ही तेज हवा में उड़ गई और छत की कई ईंटें नीचे सड़क पर जा गिरी तो कई हवा में लटकने लगी। अभी करीब चार माह पूर्व ही 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेलवे ट्रांजिट सिस्टम के 13 किमी लंबे जिस सेक्शन का उद्घाटन किया था। न्यू अशोक नगर स्टेशन भी उसी स्टेशन के बीच आने वाला एक प्रमुख स्टेशन है। और यह नव निर्मित रेलवे स्टेशन आंधी-तूफान का एक झटका भी नहीं झेल पाया। दिल्ली के न्यू अशोक नगर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से जोड़ने वाली इस परियोजना में 4600 करोड़ रुपये की लागत आई है।

आतंकी हमले के दोषियों की खोज आसान नहीं

यह सही है कि जिस प्रकार की भौगोलिक संरचना बेसरन घाटी से सटे जंगलों की है उसमें किसी की तलाश करना मुझे में सुई को खोजने जैसा हो सकता है। लेकिन इन आतंकियों द्वारा सेटेलाइट इमेज और रेकी कर के घटना को अंजाम दिया गया और सुरक्षित भाग निकलने का रास्ता सेटेलाइट फोटो से समझ लिया गया तो हम इसमें नाकाम क्यों हो जा रहे हैं कश्मीर के अंदर ही तमाम अंडरग्राउंड वर्कर माने जाने वाले युवकों को जांच एजेंसियो ने उठाया है क्योंकि यह माना जा रहा है कि बिना स्थानीय लोगों की मदद के पाकिस्तान से आकार यह घटना करना नामुमकिन था। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए कश्मीर घाटी में व्यापक अभियान चलाये जा रहे हैं, इसके बावजूद कोई परिणाम सामने नही आ पाया है। एजेंसियों ने बेसरन घाटी तक पहुंचाने और पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों को भी अपने जांच के दायरे में रखा है। एनआईए ने जिन तीन संदिग्धों के 'स्केच' जारी किए उनकी पहचान अनंतनाग निवासी आदिल हुसैन धोकर और दो अन्य पाकिस्तानी नागरिक अली भाई उर्फ तल्हा भाई और हाशिम मुसा उर्फ सुलेमान के रूप में की गई है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि- उन्हें बैसरन घाटी में निर्मम हत्या करने के बाद जमीन उन्हें निगल गई या आसमान खा गया।



जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम का बेसन घाटी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। आतंकियों के हमले से कराह उठी और इन आतंकियों ने भारतीय 26 पर्यटकों की हत्या की वह भी पत्नियों के बच्चों के सामने) इन आतंकियों के बारे में कहा गया कि वे पाकिस्तान से आए थे। इस आतंकी हमले के बाद यह आतंकी कहां गायब हो गए इस विषय सभी जांच और सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथ नजर आ रही हैं। एक जवान जिसके बारे में कहा जाता है कि वे उन आतंकियों के बहुत करीब पहुंच चुके थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई इसके बाद से कोई भी सुराग अभी ऐसा नहीं है जिससे यह कहा जा सकता है कि जिन आतंकियों ने इस प्रकार के आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था और लगभग एक घंटे तक वे बैसरन घाटी में मौजूद लोगों को इत्मीनान से मारते रहे उसने बहुत से सुरक्षा, इंटेलिजेंस और अन्य सवालों को जन्म दिया है। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया उसमें भी तीन बड़े आतंकी जो भारत में कांधार-अपहरण की घटना, 26/11 के मुंबई हमले और अन्य घटनाओं के मास्टर माइंड बताए जाते थे उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और वे पाकिस्तान में मौज कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा यह घोषणा सरकार और सेना ने किया जाता है इसी के साथ सेना ने अपनी बीजिंग में भी यह कहा था कि - हमने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिस देश की सेना ही आतंकवाद फैला रही हो उन-उन अड्डों को बनाते कितना समय लगेगा। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि पाकिस्तान में सिर्फ सो आतंकी थे जो मारे खा चुके हैं। इसलिए उनके लिए नए आतंकी मिलना हो जाएंगे। वे तो रक्तबीज की तरह है जहां एक मरता है और कई पैदा होते हैं। जिन आतंकी ठिकानों को पाकिस्तान में भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के तहत नष्ट किया उसमें लगभग सौ आतंकियों की मौत बताई जा रही है। पाकिस्तान के भारत के सैन्य नागरिक हमलों के जवाब में भारत ने जो कार्रवाई की उसने पाकिस्तान को चोट पहुंचायी है लेकिन जिन आतंकियों ने बैसरन घाटी में निर्मम हत्याएं की थी उनका पता आज तक नहीं चल सका है। जब इंटेलिजेंस के फेल होने की बात की जाती है तो वहीं यह भी कहा जा जाता है कि इन आतंकियों द्वारा चीनी सेटेलाइट फोन इस्तेमाल किए जा रहे थे जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से था इसलिए, खुफिया सूत्रों की सीमा बंध जाती है। देश भर में पाकिस्तान को जानकारी देने वाले जासूसों को खोजने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है और ऐसे लोगों का उनके कबूलनामे और डिजिटली सक्रिय होने की स्थितियों को लेकर जेल में डाल दिया गया है जिसकी असलियत कुछ वर्षो के बाद पता चलेगी कि वे क्या कर रहे थे। किसी भी आतंकी घटना में वास्तविक दोषियों की खोज बहुत आसान नहीं होती है। बहुत कम मामले ऐसे ही सामने आते हैं। जब लोग मौके पर ही पकड़ लिए जाते है जैसा कि - मुंबई हमले में हुआ। अधिकांशतः ऐसे मामलों में या तो कार्रवाई में मारे जाते हैं। या फिर वे भाग जाते हैं। देखना है कि जांच एजेंसियों द्वारा बेसरन घाटी में आतंकी हमले करके निर्मम हत्याएं करने वाले पाकिस्तानी आतंकी कब पकड़े जा सकेंगे। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ संभवतः एक मात्र ऐसा आतंकी हमला था जिसमें हमला करने वाले आतंकी या तो मारे गए थे या फिर पकड़े गए थे। यदि वह देश के अंदर है तो देर-सवेर मिल सकते हैं लेकिन यदि वे बार्डर पर कर गए तो फिर उन तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि आतंकियों के आका अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जिन्हें भारत मांगता रहा है।

देशभर के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने पर विचारण कीआवश्यकता

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कोटा में हुई छात्रों की मौत पर सुनवाई की। इन पर चिंता जाहिर की। स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई, जबकि अकेले कोटा ही नहीं देशभर के छात्रों की मौत पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन मौत की जांच होनी चाहिए। देशभर के छात्रों की आत्महत्या और इनको रोकने पर विचार होना चाहिए।

स्टूडेंट्स सुसाइड मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कोटा में हो रहे स्टूडेंट्स सुसाइड के मामलों को भी गंभीर बताया और राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, 'कोटा में इस साल अब तक 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। आप एक राज्य के तौर पर इसे लेकर क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? एक राज्य के तौर पर क्या आपने इस पर कोई विचार नहीं किया?' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कोटा में छात्रा का शव मिलने और आईआटी खड़गपुर के छात्र के सुसाइड मामले की सुनवाई के दौरान की। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी।

चार मई को एनइइटी एग्जाम से कुछ ही घंटे पहले कोटा के हॉस्टल में 17 साल की छात्रा का शव मिला था। चार मई को ही, आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले 22 साल के स्टूडेंट ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छह मई को स्वतः संज्ञान लिया था।

आईआईटी खड़गपुर सुसाइड को लेकर कोर्ट ने 14 मई को कहा था वो सिर्फ यह पता लगाने के लिए संज्ञान ले रहे हैं कि प्रशासन ने 'अमित कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य' मामले में जारी कोर्ट के निर्देशों का पालन कर एफआईआर दर्ज कराई है या नहीं। वहीं, कोटा में हुए सुसाइड को लेकर कोर्ट ने जवाब मांगा था कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने ये सुनवाई की थी। इसी के साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश भी दिया था कि मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन के लिए बनने वाली नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ के गठन के लिए 20 लाख रुपए दो दिन में जमा कराएं। बात पिछले सालों की करें, तो साल 2024 में कोटा में रहने वाले 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। पिछले साल जनवरी के महीने में 2 और फरवरी के महीने में 3 सुसाइड हुए थे। वहीं साल 2023 में कोटा में स्टूडेंट सुसाइड के कुल 26 मामले सामने आए थे।

एमपी सुसाइड प्रिवेंशन टास्क फोर्स के मेंबर और साइकेट्रिस्ट डॉ सत्यकांत त्रिवेदी ने कोटा में हो रहे स्टूडेंट सुसाइड को लेकर कहा, ह्यकिसी भी आत्महत्या का कोई एक कारण नहीं होता। वही एग्जाम सभी बच्चे दे रहे होते हैं। ऐसे में सुसाइड के लिए मिले-जुले फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। इसमें जेनेटिक्स कारण, सामाजिक कारण, पियर प्रेशर, माता-पिता के एक्सपेक्टेशन्स, शिक्षा तंत्र सब शामिल है।

डॉ त्रिवेदी कहते हैं कि कहीं न कहीं हम बच्चों को ये सिखाने में नाकामयाब हो जाते हैं कि स्ट्रेस, रिजेक्शन या फेलियर से कैसे डील करना है। आज बच्चा ये मानने लगा है कि उसका एकेडमिक अचीवमेंट उसके एग्जिस्टेंस से भी बड़ा है। बच्चा तैयारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जीवन छोड़ने के लिए तैयार है। सोसायटी ने प्रतियोगी परीक्षाओं को बहुत ज्यादा महिमामंडित कर दिया है जिसकी वजह से बच्चा ये महसूस करता है कि मैं पूर्ण तभी हो सकूंगा जब कोई एग्जाम क्रैक कर लूंगा।

देश में आत्महत्या के हर साल आने वाले मामलों में छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या की थी, जबकि, साल 2022 में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं 2018 से 2020 के दौरान कुल 33,020 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। भारत युवाओं का देश है। यहां की 60 फीसदी से ज्यादा आबादी युवा है, लेकिन, अब इसी देश में हर 40 मिनट में एक युवा अपनी जान दे रहा है। ये आंकड़े स्टूडेंट सुसाइड- एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट की ओर से जारी किए गए हैं। दरअसल, देश में हर दिन 35 से ज्यादा छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। साल 2018 से 2022 तक देश में 59,153 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

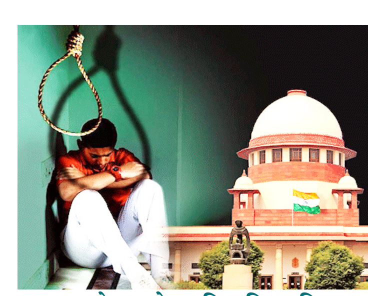
स्टूडेंट सुसाइड- एन एपिडेमिक स्वीपिंग इंडिया रिपोर्ट, आईसी थ्री की साला कॉन्फ्रेंस में साझा की गई। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। आईसी– 3 एक नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है।

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में जहां आत्महत्या की दर हर साल दो फीसदी की दर से बढ़ रही है, वहीं छात्रों में आत्महत्या की दर चार फीसदी की दर से हर साल बढ़ रही है। यानी देश में आत्महत्या के जितने मामले हर साल आते हैं, उनमें छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2021 में 13,089 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि, साल 2022 में 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की। वहीं 2018 से 2020 के दौरान कुल 33,020 छात्रों ने आत्महत्या की।

छात्रों की आत्महत्या के अलग-अलग मामलों में अलग-अलग वजहें हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में सिर्फ एक वजह है। ये वजह है मेंटल हेल्थ। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में 15 से 24 साल का हर सात में से एक आदमी खराब मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहा है।

सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग अपनी मेंटल हेल्थ की समस्या को गंभीरता से नहीं लेते, यूनिसेफ के इस सर्वे में ही जितने लोगों ने भाग लिया, उसमें से सिर्फ 41 फीसदी लोग ही अपनी मानसिक समस्या के समाधान के लिए काउंसलर के पास गए। यानी 59 फीसदी लोगों ने इस समस्या को जैसे का तैसा छोड़ दिया।

देश को चाहिए कि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों की कोई प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई संस्था बनाए तो तकनीकि शिक्षा के लिए कोचिंग करने वालों और तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं के मानसिक स्तर की समय-समय पर जांच करे। उनकी कोंसलिंग करे। उनकी समस्याओं पर विचार कर छात्र–छात्राओं का सही मार्ग दर्शन करे, ताकि वह आत्महत्या न कर, विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करना सीखें। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई जाए। अगर विशेषज्ञ समझें तो कोचिंग करने वाले और तकनीकि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को मेडिटेशन या ध्यान से भी जोड़ा जा सकता है। इससे युवाओं में विषय के प्रति एकाग्रता बढ़ेगी। चिंतन शक्ति का विकास होगा। निगेटिव विचार कम होंगे। ये मेडिटेशन या ध्यान उन्हें पूरे जीवन के लिए नई ऊर्जा प्रदान करेगा।



देश को चाहिए कि वरिष्ठ मनोवैज्ञानिकों की कोई प्रदेश स्तर पर ऐसी कोई संस्था बनाए तो तकनीकि शिक्षा के लिए कोचिंग करने वालों और तकनीकि शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र–छात्राओं के मानसिक स्तर की समय-समय पर जांच करे। उनकी कोंसलिंग करे। उनकी समस्याओं पर विचार कर छात्र–छात्राओं का सही मार्ग दर्शन करे, ताकि वह आत्महत्या न कर, विपरीत परिस्थिति से संघर्ष करना सीखें। उन्हें जीवन जीने की कला सिखाई जाए।



एमएसपी घोषणा सकारात्मक पहल तो चाकचैबंद खरीद व्यवस्था भी जरुरी

केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा खरीफ की बुवाई से पहले ही करने को किसानों के हित में सकारात्मक पहल के रुप में देखा जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा एक तो समय पूर्व समर्थन मूल्यों की घोषणा की जा रही है वहीं दूसरी और भविष्य की रणनीति के तहत आवश्यकतानुसार उत्पादन बढाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा श्री अन्न को जहां अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने का सफल प्रयास किया गया है वहीं देश को दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है तो तिलहन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आगामी खरीफ के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों में रामतिल के भावों में सर्वाधिक 820 रु. की बढ़ोतरी करते हुए 9537 रु. प्रति क्विंटल एमएसपी घोषित की गई है। इसी तरह से तिल की एमएसपी में 579 रु., सोयाबीन में 436 रु., सूरजमुखी में 441 रु. और मूंगफली की एमएसपी में 480 रु. की बढ़ोतरी की गई है। ठीक इसी तरह से उड़द में 400 रु. तो मूंग की एमएसपी में 86 रु. और अरहर की एमएसपी में 450 रु. की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह से बाजरा, रागी, ज्वार, कपास, धान आदि अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी की गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक एमएसपी दरों की घोषणा की बात है सरकार की ईच्छा शक्ति पर कि सी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार के 2013-14 से 2025-26 तक के कार्यकाल की एमएसपी दरों में बढ़ोतरी निश्चित रुप से सकारात्मक दिषा में बढ़ता कदम माना जा सकता है। 2013-14 की तुलना में 226 प्रतिशत की बढ़ोतरी रागी के समर्थन मूल्य में की गई है। बाजरा में 122 प्रतिशत तो ज्वार की एमएसपी में 147 प्रतिशत तक की बढोतरी हो चुकी है। दलहन और तिलहन की खरीफ फसलों में भी 82 प्रतिशत से रामतिल में 172 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सरकार का यह भी दावा है कि एमएसपी घोषणा करने से पहले सरकार ने फसलों की लागत के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा है और लागत से कहीं अधिक एमएसपी दर जारी की गई है।

किसान आंदोलनों के दौरान सबसे अहम मुद्दा एमएसपी को लेकर ही रहता आया है। सरकार एक और एमएसपी दरों में बढ़ोतरी और एमएसपी पर खरीद का दावा कर रही है और यह दावा एक हद तक सही भी है पर दूसरी और किसान नेताओं का यह कहना रहा है कि सरकार एमएसपी दरों की घोषणा के साथ ही एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। केन्द्र सरकार की औंर से एफसीआई और नेफैड एमएसपी खरीद के लिए नोडल संस्था है तो कपास की खरीद सीसीआई द्वारा की जाती है। राज्यों में एफस-ीआई व नेफैड के लिए खरीद सुविधा में राज्यों की सहकारी विपणन संस्थाएं प्रमुखता से सहभागी रहती है। खरीद की व्यवस्था को भी पारदर्शी और ऑनलाईन कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन से लेकर सीधे खातों में भुगतान तक की व्यवस्था ऑनलाईन की गई है। पर कहीं ना कही व्यवस्था में झोल अवश्य है। इसको यों समझा जा सकता है कि एक समय था तब सरकारी खरीद शुरु होने की घोषणा और लगभग 10 से 15 प्रतिशत उत्पादन की खरीद होते होते मण्डियों में भाव एमएसपी के आसपास आ जाते थे। इसका परिणाम यह होता था कि ना तो किसानों की नाराजगी रहती थी और ना ही अन्य कोई समस्या आती थी। पर आज खरीद व्यवस्था के पारदर्शी होने के बावजूद किसान अपने आप को ठगा महसूस करता है। इसका एक बड़ा कारण तो यह है कि बाजरा आदि की खरीद तो सरकार द्वारा किसी ना किसी बहाने टाली ही जाती है क्योंकि बाजरे की खरीद के बाद रखरखाव को लेकर संकट रहता है और सरकार का मानना है कि उसे नुक- सान अधिक होता है क्योंकि खरीदा हुआ बाजरा जल्दी खराब हो जाता है। वहीं दूसरी और व्यवस्था को लाख पारदर्शी और जबावदेह बनाने के बावजूद बिचौलियें इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाते देखे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो खरीद केन्द्रों पर जितनी मात्रा में खरीद हो रही है वह उस क्षेत्र में उत्पादित पैदावार से भी अधिक हो जाती है। इसके साथ ही किसानों की तात्कालीक आवश्यकताओं के चलते आड़तियों पर निर्भरता के कारण भी किसान का लाभ आड़तियां ले जाता है। हांलाकि यह व्यवस्था का ही दोष माना जा सकता है। होना तो यह चाहिए कि जिन फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है उन फसलों के तैयार होकर मण्डियों में आने से पहले ही सरकार को खरीद की आवश्यक तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। खरीद के लिए खरीद केन्द्र की स्थापना, तुलाई ढुलाई की व्यवस्था, बारदाना, ट्रांसपोर्टेशन, भण्डारण, भुगतान की आवश्यक व्यवस्था, बैंकों से भुगतान आदि की व्यवस्था, खरीद केन्द्रों पर पीने के लिए पानी आदि की व्यवस्था सहित आवश्यक सभी तैयारियां सुनिश्चित हो जानी चाहिए। इसके साथ ही आज सरकार के पास उत्पादन के सारे डेटा उपलब्ध होते हैं ऐसे में संभावित खरीद का आकलन भी सुनिश्चित हो जाना चाहिए। सरकार द्वारा पूर्व में ही यह घोषणा कि इतनी मात्रा में ही खरीद की जाएगी तो इससे राजनीति के अधिक अवसर उत्पन्न हो जाते हैं और अनावश्यक भ्रम के हालात बन जाते हैं। ऐसे हालात से बचा जाना जरुरी हो जाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को खरीफ श्री अन्न खासतौर से बाजरा आदि की खरीद की भी स्पष्ट नीति बनानी होगी अन्यथा श्री अन्न खासतौर से बाजरा को हम अंतराष्ट्रीय प्लेटफार्म दिला रहे हैं वह जल्दी ही प्रभावित हो सकती है। सरकार को कोई ना कोई ऐसी स्पष्ट रणनीति बनानी होगी जिससे बाजरा उत्पादक किसान एमएसपी दर घोषित होने के बावजूद अपने आपको ठगा महसूस ना कर सके। इसके लिए बाजार ताकतों को भी सक्रिय करना होगा ताकि बाजार में श्रीअन्न बाजरा आदि की मांग बढ़े और सरकारी खरीद ना होने की स्थिति में भी एमएसपी दर तो कम से कम उत्पादक किसान को बाजार में मिल सके। इस-के लिए सरकार को इच्छाशक्ति के साथ आगे आना होगा। अब श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने का हमारा दायित्व भी हो जाता है ऐसे में इस और अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तो बुवाई से फसल पकने तक का तीन से चार माह का समय सरकार के पास होगा।

इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को भी ठोस प्रयास करने होंगे ताकि इस समस्या का समाधान खोजा जा सके और अन्नदाता को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। देर सबेर सरकार को खरीद को सीमा में बांधने के स्थान पर स्थाई हल खोजना होगा ताकि एमएसपी व्यवस्था और अधिक किसान हितेषी हो सकें।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

समाचारों के बढ़ते साधन गिरता स्तर

भारत में पत्रकारिता एक समय पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती थी। समाज की आवाज उठाने, सत्ता से सवाल पूछने और जनभावनाओं को मंच देने में इसकी भूमिका अविस्मरणीय रही है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में पत्रकारिता का स्तर चिंताजनक रूप से गिरा है, जबकि पत्रकारों की प्रसिद्धि, प्रभाव और पहुंच पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह विरोधाभास क्यों? पत्रकार बड़े होते जा रहे हैं, पर पत्रकारिता क्यों सिकुड़ रही है? आज फेसबुक पत्रकार, न्यूज पोर्टल चलाने वाले पत्रकार ,यूटयूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों की देश में बाढ़ सी आ गई है। दैनिक अखबार भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन समाचार पत्रों की रोज गिनती बढ़ती जा रही है। जिसे देखो पत्रकारिता कर रहा है। इतना सब होने के बावजूद पिछले कुछ साल में खबर की विश्वसनीय घटी है। पत्रकारिता का स्तर गिरा है। पत्रकार का सम्मान घटा है। पहले माना जाता कि अखबार में छपा है तो सही होगा, किंतु मीडिया में आई खबर की आज कोई गारंटी देने को तैयार नहीं। आज का पत्रकार खबर लिख रहा है किंतु खबर की गांरटी से भाग रहा है। वह यह दावा करने को कोई तैयार नही कि जो खबर उसने लिखी है, वह सही है। विश्वनीय है। जब तक खबरों को चेहरों से बड़ा नहीं समझा जाएगा और पत्रकारिता को फिर से जनसेवा के रूप में नहीं देखा जाएगा, तब तक यह गिरावट जारी रह सकती है।

पत्रकारिता के नए हाल पर न्यूज पोर्टल और यूटयूब चैनल पर चलती फर्जी खबरों का लेकर देश के लगभग 20 अखबारों ने एक अभियान शुरू किया है। इसके तहत वे प्रचार कर रहे हैं कि न्यूज पक्की और सच्ची खबर—प्रिंट मतलब पक्का सबूत। इन्होंने ये अभियान तो शुरू किया किंतु अभियान चलाते समय वे ये भूल गए कि वे भी फेसबुक और यूटयूब चैनल चला रहे हैं, इतना जरूर है कि इनके पास प्रोफेशनल की टीम है, इसलिए इनकी खबरें ज्यादा प्रभाणित है, ज्यादा विश्वसनीय हैं।

पत्रकारिता कभी मिशन था। आजादी के आंदेलन तक मिशन रहा। धीरे—धीरे इसमें व्यापारी आने लगे। औद्योगिक घराने उतर गए। इनका उद्देश्य समाज सेवा नही रहा, व्यापार हो गया। ये व्यापार करने लगे। वह छापने लगे जिस्से इन्हें लाभ हो। इन्होंने पत्रकारिता और अखबारों के नाम पर दुकानें खोल लीं। लेकिन इन्होंने समाज की जरूरतों का ध्यान रखा। करोड़ों रुपए लगाकर ये सर्वे कराते कि किस उम्र का पाठक क्या पढ़ना चाहता है, उस रिपोर्ट के आधार पर ये खबरे कराते। लेख लिखाते। बस अपने हितों का ध्यान रखते। इन प्रतिष्ठानों को पैसा मिलने लगा तो इनसे जुड़े पत्रकारों और कर्मचारियों को आकर्षक वेतन और कमीशन मिलने लगे। मिशन की भावना पत्रकारिता से गायब हो गई। मीडिया संस्थान अब स्वतंत्र नहीं रहे। बड़े मीडिया हाउस कॉरपोरेट पूंजी से संचालित हो रहे हैं और कई बार सरकार के नजदीक दिखते हैं। इससे खबरों की निष्पक्षता और निर्भीकता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। नतीजा—जांच रिपोर्टिंग, जमीनी सच्चाई और सत्ता से सवाल पूछने की परंपरा लगभग गायब होती जा रही है।

गांव देहात से छोटे-मोटे पत्रकार अब भी मिशन के तहत लगे थे। डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम के किस्से भी स्थानीय ऐसे ही एक सांध्य दैनिक समाचार पत्र से प्रकाश में आए। सिरसा के सांध्य दैनिक 'पूरा सच' के संपादक रामचंद्र छत्रपति, राम रहीम और डेरा सच्चा सौदा पर आश्रम में होरही खबरें लिख रहे थे। वहां हो रहे कारनामों का भांडाफोड़ कर रहे थे। उन रामचंद्र छत्रपति को गोलियां मारी गईं। हत्या करा दी गई। आरोप राम रहीम पर आया। सीबीआई जांच हुई और अपराध साबित हुआ। समय तेजी से बदल रहा है। आज पत्रकार अपना न्यूज पोर्टल ही नही चला रहे। यूटयूब चैनल चला रहे है। फेसबुक लाइव पर लगे है। रोज नए ब्लागर पैदा हो रहे है। आज का पत्रकार खुद एक ह्यब्रांडह्न बन चुका है। सोशल मीडिया ने रिपोर्टिंग को व्यक्ति-केंद्रित बना दिया है। पहले खबरें केंद्र में होती थीं, अब पत्रकार। टीवी डिबेट्स और यूट्यूब चैनलों पर पत्रकार अपनी पहचान, विचारधारा और नाटकीयता को प्राथमिकता देते हैं। खबर से ज्यादा चर्चित चेहरा बनना आज का लक्ष्य बन गया है। पहले विज्ञापन के लिए उद्योगपतियों की ओर देखना पड़ता था, अब ऐसा नही है। अब आपकी साम्रग्री के हिसाब से गूगल भुगतान कर रहा है। जिनकी सामग्री अलग और नई है, वे मौज ले रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि कुछ अपने लाइक लेने, व्यूज और टीआरपी की दौड़ में मीडिया अतिंरजित खबरे चला रहा है। उसे खबरों के पुष्ट करने का समय नही।फर्जी खबरे चल रही हैं। अभी आपरेशन सिंदूर के दौरान किसी ने खबर चला दी कि भारतीय सैना पाकिस्तान में प्रवेश कर गई तो एक ने चला दिया कि भारत का लाहौर पर कब्जा हो गया। जबकि ऐसा कुछ नही था।

डिजिटल युग में टीआरपी और व्यूज ही सफलता का पैमाना बन गए हैं। गंभीर पत्रकारिता की जगह सनसनीखेज खबरें, गॉसिप, और ह्यडिबेट तमाशाह्न ने ले ली है। तथ्य की जगह धारणा, विश्लेषण की जगह उत्तेजना, और संवाद की जगह शोर ने कब्जा कर लिया है। एंकर शोर मचाकर चीखकर पाठकों को आकृषित करन में लगे हैं। खबरों के हैंडिग गलत लगाकर पाठक को खबर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि खबरों में हैंडिंग के अनुरूप कुछ नही होता। इससे पत्रकारिता का स्तर और विश्वसनीयता तेजी से गिर रही है। अखबारों में झूठी खबरों को रोका जाता था। कोशिश रहती कि खबरों की विश्वसनीयता बनी रहे। व्यक्तिवादी तंत्र में अब ऐसा नही हो रहा। जल्दी दिखाने की होड़ में और टीआरपी बटोरने के लिए आधी—अधूरी खबरे चलने लगी है। मुंबई पर आतंकवादी हमले और कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान मीडिया ने कुछ ऐसी खबरे चलाईं जिससे दुश्मन और आंतकवादियों को ज्यादा लाभ हुआ। इन्होंने देश हित नही देखा। मुंबई हमले को चैनल द्वारा लाइव दिखाने के कारण पाकिस्तान में बैठे हमलावरों के आका चैनल देखकर आंतकवादियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। इसकी आलोचना भी हुई। मीडिया के लिए दिशा—निर्देश बनाने की मांग भी हुई। धीरे—धीरे गांव-कस्बों की खबरें गायब हो चुकी हैं। रिपोर्टर अब स्टूडियो में बैठकर 'नेरेटिव' बनाते हैं। ग्राउंड पर जाने की जहमत नहीं उठाते। इससे पत्रकारिता का मूल उद्देश्य–जनता की आवाज को मंच देना–कमजोर हो गया है। अब ये जरूरी होता जा रहा है कि मीडिया में आने वाले पत्रकारिया या वीडियो पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेकर आए। नए शासनादेश, देश हित और कानून की उन्हें जानकारी हो। सरकार द्वारा प्रत्येक पत्रकार के लिए ये प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए। बार कौंसिल की तरह पत्रकार कौंसिल जैसी संस्था बने जो पत्रकारों पर नजर रखे। उनके लिए दिशा—निर्देश तैयार करे। ऐसा होता है तो सरकार को मीडिया पर नियंत्रण की जरूरत नही पड़ेगी। वरन सरकार को इस पर नियंत्रण के लिए कभी न कभी दिशा निर्देश जारी ही करने होंगे। जैसे की अभी आपरेशन सिंदुर के समय जारी किये गए। नवोदित पत्रकारों के लिए पत्रकारिता अब 'मिशन' नहीं बल्कि 'कैरियर' बनती जा रही है। कई संस्थानों में उन्हें बहुत कम वेतन पर काम कराया जाता है, जिससे उनमें पेशे के प्रति समर्पण घटता है। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों का आभा मंडल इतना विशाल हो गया है कि नए लोगों को उभरने का मौका कम मिलता है। इसलिए जरूरत है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा मिले। पब्लिक फंडिंग या सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए।नए पत्रकारों को प्रशिक्षण और संरक्षण मिले। ग्राउंड रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाए।

जनसंचार का सशक्त माध्यम है हिन्दी पत्रकारिता

पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा ने लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका के बारे में कहा था कि प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अखण्डता के संदर्भ में पत्रकारिता की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र के अन्य स्तंभों के मुकाबले प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्वभर में भारत की प्रतिष्ठा के जो तीन प्रमुख कारण माने गए हैं, वे हैं जागरूक मतदाता, स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र प्रेस। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी ह्यसंसदह्न की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए ही कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने का अथवा उसे जागृत करने के लिए जन संचार का सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं व विचारों को समझना और उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। वैसे भारत-पाक युद्ध का उल्लेख करें अथवा भारत-चीन लड़ाई का या अन्य चुनौतीपूर्ण अवसरों का, प्रेस ने ऐसे हर अवसर पर अपनी महत्ता सिद्ध की है और कहना गलत न होगा कि हिन्दी पत्रकारिता का स्थान इसमें सर्वोपरि रहा है। चाहे हिन्दी भाषी टीवी चैनलों की बात हो या हिन्दी के समाचारपत्र अथवा पत्रिकाओं की, उनका देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ विशेष जुड़ाव रहा है और इस दृष्टि से राष्ट्र की एकता, अखण्डता एवं विकास की दिशा में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि हिन्दी पत्रकारिता के 199 वर्षों के इतिहास में समय के साथ पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य बदलते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद सुखद स्थिति यह है कि हिन्दी पत्रकारिता के पाठकों या दर्शकों की रूचि में कोई कमी नहीं आई। यह अलग बात है कि अंग्रेजी मीडिया और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों ने भले ही हिन्दी पत्रकारिता की उपेक्षा करते हुए सदैव उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें की हैं किन्तु वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ दशकों में हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी ताकत का बखूबी अहसास कराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यह हिन्दी पत्रकारिता की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि कुछ हिन्दी अखबारों ने अनेक संस्करणों के साथ प्रसार संख्या के मामले में कुछ अंग्रेजी अखबारों को भी पीछे छोड़ दिया है।

हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड के प्रकाशन के साथ हुई थी, जिसका अर्थ था समाचार सूर्य। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र उदन्त मार्तण्ड 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था, जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छापी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे, इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया। 4 दिसम्बर 1826 से उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। उदन्त मार्तण्ड के बाद अंग्रेजी शासनकाल में अनेक हिन्दी समाचारपत्र व पत्रिकाएं एक मिशन के रूप में निकलते गए किन्तु ब्रिटिश शासनकाल की ज्यादतियों के चलते उन्हें लंबे समय तक चलाते रहना बड़ा मुश्किल था, फिर भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने सराहनीय सफर तय किया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और हिन्दी पत्रकारिता भी मिशन न रहकर एक बड़ा व्यवसाय बन गई है किन्तु अच्छी बात यह है कि आज भी हिन्दी पाठक व दर्शक अपनी-अपनी पसंद के अखबारों व चैनलों के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हैं।

बहरहाल, घर बैठे-बैठे दुनिया की सैर कराने की बात हो या देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी हलचल से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों और हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों को जुटाकर अपने पाठकों या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की, व्यवसायीकरण के आरोपों या तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिन्दी पत्रकारिता यह काम बखूबी कर रही है और आमजन के भरोसे पर खरा उतरते हुए हिन्दी पत्रकारिता आज आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। अधिकांश हिन्दी समाचारपत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पदार्फाश करके अनेक सफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैंकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता।

जहां तक राष्ट्रीय अखंडता में प्रेस की भूमिका और इसके दायित्वों का प्रश्न है तो प्रेस के कई प्रमुख दायित्व माने गए हैं, जिनमें कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पदार्फाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पदार्फाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि शामिल हैं। वर्तमान में जहां देशभर में नैतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है और राजनीतिज्ञों, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, वहीं हिन्दी पत्रकारिता भी इस नैतिक पतन का शिकार होने से नहीं बची है। फिर भी इतना संतोष तो किया ही जा सकता है कि इसने इसके बावजूद अधिकांश अवसरों पर सराहनीय भूमिका निभाई है। हालांकि आज के पूर्ण व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता को अव्यावसायिक बनाए रखने की बात करना बेमानी होगा क्योंकि इस पेशे से जुड़े लोगों को भी अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना अनिवार्य होता गया है लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में भी इसे एक उद्योग-धंधे के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के चलते पत्रकारिता के मानदंडों को ताक पर रखने की प्रवृति से तो हर हाल में बचना ही चाहिए।

अंधड़, बारिश और चेतावनी: बदलता मौसम, बिगड़ता संतुलन

गत दिनों 24-25 मई की रात उत्तर भारत के लिए एक बार फिर ऐसी रात बनकर आई, जिसने न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत को झकझोरकर रख दिया। इस प्रचंड मौसमीय तांडव ने न केवल जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया बल्कि एक बार फिर यह संकेत दे दिया कि अब मौसम चक्रों में स्थायित्व नहीं रहा और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे सिर पर मंडरा रहा है। एक ओर जहां लोगों को चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली, वहीं दूसरी ओर भीषण बारिश और तेज हवाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया। मई महीने में जब उत्तर भारत 44-45 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी के लिए जाना जाता है, ऐसे समय में अचानक ऐसे तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि जैसे दृश्य आमतौर पर मानसून के चरम काल में भी दुर्लभ होते हैं। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने इस तूफान से पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था परंतु तूफान की तीव्रता और व्यापक प्रभाव ने पारंपरिक मौसमी पूवार्नुमानों को भी पीछे छोड़ दिया। रविवार की देर रात तेज हवाओं ने पूरे दिल्ली-एनसीआर में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा से तेजी से बढ़ते तूफानी बादल महज कुछ ही घंटों में दिल्ली-एनसीआर की ओर आ गए। आसमान में अचानक तेज बिजली चमकने लगी, फिर गरज के साथ बारिश शुरू हुई और देखते ही देखते स्थिति एक शक्तिशाली तूफान में बदल गई। हवा की रफ्तार इतनी अधिक थी कि कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, ट्रैफिक सिग्नल गिर गए, बिजली के खंभे झुक गए और कई वाहनों को क्षति पहुंची। आईएमडी के अनुसार, इस दौरान हवा की गति 60 किमी प्रतिघंटा तक पहुंच गई थी और कुछ स्थानों पर तो यह इससे भी अधिक रिकॉर्ड की गई। केवल दिल्ली ही नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के प्रमुख शहरों में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। गुरुग्राम में तेज हवा के कारण कई जगहों पर निमार्णाधीन साइटों की छतें उड़ गई जबकि नोएडा में एक निमार्णाधीन बिल्डिंग की क्रेन गिरने से दो लोग घायल हो गए। उत्तर भारत के अन्य भागों, जम्मू, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान में भी यह तूफान तबाही लेकर आया। जगह-जगह सैंकड़ों पेड़ उखड़ गए, जिससे कई जगहों पर सड़कों का संपर्क टूट गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने की घटना भी सामने आई, जहां सात वाहन बह गए और कई अन्य क्षतिग्रस्त हो गए। पंजाब में वर्षाजनित हादसों में कुछ लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई। खेतों में काम कर रहे किसान तेज आंधी की चपेट में आ गए। इससे पहले 21 मई को भी शाम के समय अचानक दिल्ली-एनसीआर का मौसम बदल गया था और अचानक बदले मौसम के बीच भीषण आंधी-तूफान और ओलावृष्टि ने जमकर तबाही मचाई थी। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि नोएडा, गाजियाबाद सहित देश के कई राज्यों में लोगों के लिए मुसीबत बन गया था। उस दौरान हुए हादसों में 7 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि देशभर में करीब 26 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी। इस साल मई महीने की शुरूआत ही इसी प्रकार के अप्रत्याशित मौसमी बदलावों के साथ हुई थी। 2 मई की सुबह दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में तेज आंधी, बारिश और तूफान जैसी स्थिति बनी थी। दिल्ली में उस दिन 78 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली थी और बारिश के साथ भारी नुकसान हुआ था। पेड़ उखड़ गए थे, बिजली की आपूर्ति बाधित हुई थी और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि उस समय भी लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई थी लेकिन इस बार मई के अंत में आया यह तूफान कहीं अधिक गंभीर और व्यापक प्रभाव वाला था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सब केवल सामान्य मौसमी उतार-चढ़ाव नहीं हैं बल्कि जलवायु परिवर्तन के गहरे संकेत हैं। दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत में तेजी से बढ़ता शहरीकरण, औद्योगीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन अब मौसम चक्रों को अस्थिर कर रहा है। ह्यशहरी हीट आइलैंडह्न प्रभाव के चलते रात के तापमान में गिरावट नहीं होती और वातावरण की ऊष्मा बढ़ती जाती है। कंक्रीट, एस्फाल्ट और अन्य मानव निर्मित सतहें सूरज की ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और धीरे-धीरे उसे छोड़ती हैं, जिससे रात में भी वातावरण गर्म बना रहता है। 2 मई की सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि सामान्यतः ऐसी बारिश के बाद तापमान 18-20 डिग्री तक गिर जाता है। मौसम विभाग ने इस बार के तूफान के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली नम हवाओं के संगम को कारण बताया है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक: पंकज धर द्विवेदी
संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com